सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 76, नई दिल्ली । मंगलवार, 28 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है।

03 विभव बेल याचिका खारिज कोर्ट में मालीवाल रो पडी
06 नई सरकार की प्राथमिकता हो सेवा निर्यात
08 फेम ने सिंधी बाजार के व्यापारियों के साथ दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन

1 जून से देश भर में लागू होगा नया नियम
25,000 रुपये का कटेगा चालान और होगी गाड़ी भी ज़ब्त

संजय बाटला

नई दिल्ली। 1 जून 2024 से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। नियमों के अनुसार अगर कोई तेज स्पीड में वाहन चलाता है तो उसको 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति वाहन चलाते पाए जाते हैं तो 25,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। साथ ही उस नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। बता दें कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। वहीं 16 साल की उम्र पूरी होने पर 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके बाद 18 साल के होने पर आप उस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं। तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले को 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

तेज रफ़्तार: अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना: अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

नाबालिग ड्राइवर: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा और गाड़ी मालिक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

हेलमेट और सीट बेल्ट: हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर 100-100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

1 जून से प्राइवेट इंस्टिट्यूट (ड्राइविंग स्कूल) में भी ड्राइविंग टेस्ट हो सकेंगे। अभी तक टेस्ट सिर्फ आरटीओ की तरफ से जारी सरकारी सेंटर में ही होते थे। अब प्राइवेट इंस्टिट्यूट में भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा और उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। हालांकि यह टेस्ट सिर्फ उन्हीं प्राइवेट इंस्टिट्यूट में होगा जिन्हें आरटीओ की तरफ से अथॉराइज्ड किया जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता को ना तो मिला दिल्ली का पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर और ना कभी मिल सकता प्राइवेट ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टोलवा

दिल्ली भारत देश की राजधानी में परिवहन विभाग के आला अधिकारी की इच्छा के बिना ना तो दिल्ली में पंजीकरण प्राप्त कर पाया कोई भी पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर और ना ही पंजीकरण करवा पायेगा कोई प्राइवेट ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जहा दिल्ली का नागरिक जाकर अपना लाइसेंस बनवा सके।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

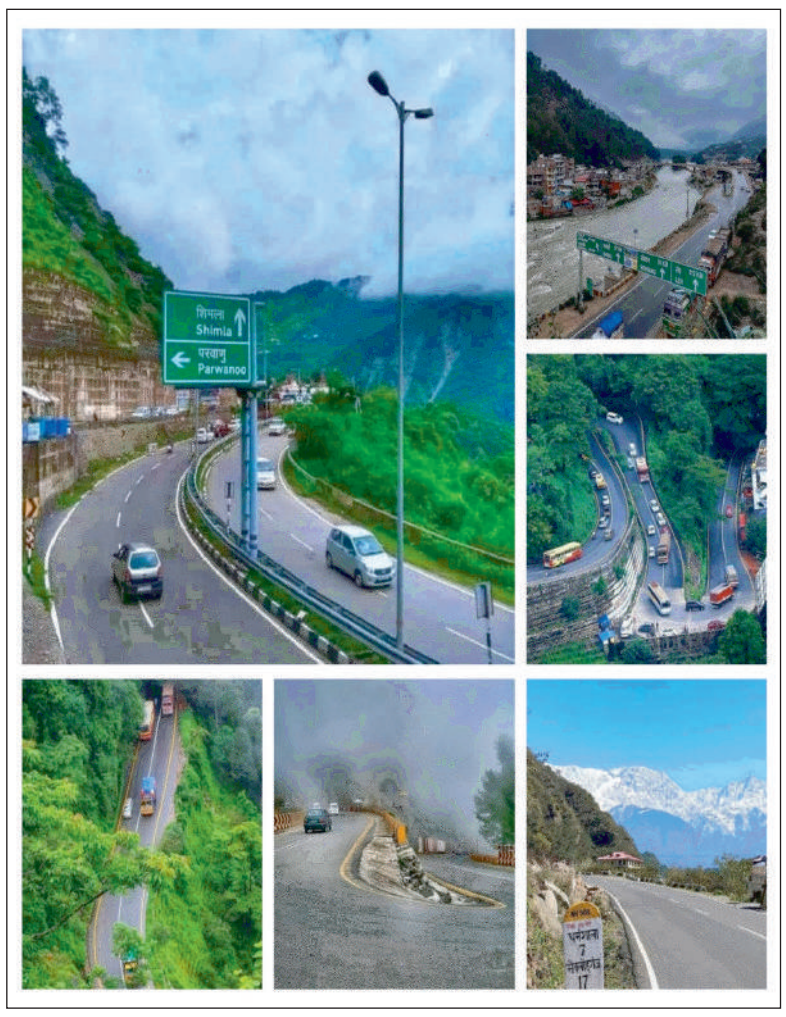

इस गर्मी की छुट्टियों में, अन्य शहरों की यात्रा करते समय- एक समझदार चालक बनें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें

गर्मी की छुट्टियों का समय आते ही लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ विभिन्न शहरों की यात्रा करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी है कि हम यातायात नियमों का पालन करें, खासकर जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चला रहे हों। यातायात नियमों की अनदेखी न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है।

सुरक्षित ड्राइविंग के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स:

गति सीमा का पालन करें: पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सामान्य सड़कों से भिन्न होती है। इसलिए, निर्धारित गति सीमा का पालन करें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।

सड़क के संकेतों का ध्यान रखें: पहाड़ों में सड़क के संकेत जैसे 'मोड़ पर धीमी गति', 'सड़क संकरी है', और 'चट्टान गिरने का खतरा' आदि का पालन करें। ये संकेत आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हैं।

ओवरटेक करने से बचें: पहाड़ी सड़कों पर ओवरटेक करना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि सड़क साफ है और सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है तभी ओवरटेक करें।

ब्रेक्स की जांच करें: पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रेक्स का सही से काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यात्रा शुरू करने से पहले ब्रेक्स की जांच अवश्य करें।

मौसम की जानकारी रखें: पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। यात्रा से पहले और दौरान मौसम की जानकारी लेते रहें।

थकान से बचें: लंबे समय तक गाड़ी चलाने से थकान हो सकती है, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। नियमित अंतराल पर रुकें और आराम करें।

आपातकालीन किट साथ रखें: पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर नेटवर्क की समस्या होती है। ऐसे में एक आपातकालीन किट जिसमें फर्स्ट एड, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, और जरूरी उपकरण हों, साथ रखें।

सावधानी से मोड़ लें: पहाड़ी सड़कों पर मोड़ बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इन्हें धीरे और सावधानीपूर्वक लें, और हमेशा हॉर्न बजाकर संकेत दें।

याद रखें, आपकी और दूसरों की सुरक्षा आपके हाथ में है। समझदारी और अनुशासन से भरी ड्राइविंग ही एक सुरक्षित यात्रा की कुंजी है। इसलिए, इस गर्मी की छुट्टियों में जब भी आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सड़क यात्रा पर निकलें, तो यातायात नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार चालक बनें। सुरक्षित यात्रा करें और अपनी छुट्टियों का आनंद उठाएं!

अपने सबसे छोटे बच्चे को बनाएं रोड सेफ्टी बडी #RoadSafetyBuddy

इस गर्मी की छुट्टियों में जब आप सड़क यात्रा पर निकलें, तो अपने सबसे छोटे बच्चे को अपना रोड सेफ्टी बडी बनाएं। बच्चों को जिम्मेदारी देने से न केवल वे उत्साहित होते हैं, बल्कि वे यातायात नियमों के पालन में भी मददगार साबित होते हैं।

जब बच्चे यात्रा के दौरान आपकी ड्राइविंग पर नजर रखते हैं, तो वे आपको लापरवाही से गाड़ी चलाने नहीं देंगे और यातायात नियमों का पालन करने में सहायता करेंगे। इससे न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बच्चे भी यातायात के महत्व को समझेंगे।

तो अगली बार जब आप यात्रा पर जाएं, अपने बच्चे को रोड सेफ्टी बडी (RoadSafetyBuddy) बनाएं और उनके साथ अपने ड्राइविंग अनुभव साझा करें। यह न केवल एक मजेदार गतिविधि होगी, बल्कि एक शिक्षाप्रद अनुभव भी साबित होगा। सुरक्षित यात्रा करें और अपने बच्चों के साथ यादगार पल बिताएं!

आपकी यात्रा के सबसे अच्छे पलों को कैमरे में कैद करें और हमें भेजें। अपने अनुभव और तस्वीरें हमें ईमेल करें: roadsafetysquad@gmail.com पर।

हम आपके संदेशों और फोटो का इंतजार कर रहे हैं! सुरक्षित यात्रा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।

डॉ अंकुर शरण, राष्ट्रीय मुख्य परिवहन एवं योजना अधिकारी
Road Safety Omni Foundation
roadsafetysquad@gmail.com

पर्यावरण पाठशाला : विश्व पर्यावरण दिवस पर सिर्फ पेड़ लगाएं नहीं, बल्कि अपनाएं और पोषण करें : अंकुर

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। हर साल, इस दिन पर हम सभी से वृक्षारोपण करने का आह्वान किया जाता है, लेकिन इस बार हमारा संदेश कुछ अलग है। केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है; हमें उन्हें अपनाना और उनके पोषण का संकल्प भी लेना चाहिए।

पेड़ लगाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उनके उचित रखरखाव और देखभाल के बिना यह प्रयास अधूरा है। इसलिए, इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जब भी आप एक पेड़ लगाएं, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। पेड़ को पौधारोपण के बाद कम से कम तीन वर्षों तक उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करें कि पेड़ के चारों ओर एक मजबूत वृक्ष रक्षक हो, जिससे वह सुरक्षित रहे और बढ़ सके।

इसके अलावा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम गुणवत्ता वाले और स्थानीय (स्थानीय) प्रजातियों के पेड़ लगाएं। स्थानीय पेड़ न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि वे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी लाभकारी होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसे क्षेत्रों में पेड़ लगाएं जहां उच्च तनाव वाली बिजली की तारें नहीं हैं, जिससे पेड़ की वृद्धि पर कोई बाधा न आए।

सही पेड़ का चयन करना भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय पेड़ों की प्रजातियाँ, जैसे नीम, पीपल, बरगद, और आम, हमारे पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और हमारे जैवविविधता को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये पेड़ न केवल छाया और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक धरोहर का भी हिस्सा हैं।

अतः इस पर्यावरण दिवस पर, आइए एक कदम आगे बढ़ें। पेड़ लगाएं, उन्हें अपनाएं, और उनकी देखभाल करें। याद रखें, एक पेड़ को अपनाना और उसका पोषण करना हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी योगदान है।

पेड़ सिर्फ हमारी धरती को हरा-भरा नहीं बनाते, बल्कि वे हमारे जीवन को भी समृद्ध करते हैं। इसलिए, चलिए इस पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ को अपनाएं और एक हरित और स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

indiangreenbuddy@gmail.com

नौकरी से निकाले जाने पर 350 क्लस्टर कर्मियों ने दिया डिम्टस मुख्यालय पर धरना...

परिवहन विशेष न्यूज

धरने की सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में 10 कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिम्ट्स कंपनी के सीईओ राकेश जैन और एवीपी अजय कुमार श्रीवास्तव से बात की। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर सरकार के साथ कंपनी के अनुबंध को विस्तार मिलता है तो कर्मचारियों को दिए गए सेवा समाप्ति के नोटिसों को वापस ले लिया जाएगा।

नई दिल्ली। सेवा समाप्ति का नोटिस मिलने के बाद दिल्ली मल्टी माडल इंटीग्रेटिड ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) के 350 कर्मचारियों ने सोमवार को अपने परिजनों के साथ कंपनी के शास्त्री पार्क स्थित मुख्यालय पर धरना दिया। कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने की बजाय उन्हें अन्य क्लस्टर डिपो में समायोजित किए जाने की मांग की। धरने की सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में 10 कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिम्ट्स कंपनी के सीईओ राकेश जैन और एवीपी अजय कुमार श्रीवास्तव से बात की। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर सरकार के साथ कंपनी के अनुबंध को विस्तार मिलता है तो कर्मचारियों को दिए गए सेवा समाप्ति के नोटिसों को वापस ले लिया जाएगा।

350 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जा रही

कर्मचारी विकास सिंह ने बताया कि डिम्ट्स ने उन्हें संविदा पर नहीं बल्कि स्थायी नौकरी दी थी। इससे पहले डिम्ट्स के तीन डिपो कुशक नाला, सुनहरी पुला और बीवीएम बंद हुए लेकिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की बजाय उन्हें अन्य डिपो में समायोजित कर दिया गया था। अब कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि बसों के चार क्लस्टरों का सरकार के साथ 19 जून को अनुबंध समाप्त हो रहा है, इसलिए यहां तैनात 350 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जा रही है।

इलेक्ट्रिक बसों के नए डिपो में किया जा सकता है समायोजित

कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से डिम्ट्स को ई बसों के क्लस्टरों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बीते साल ही मिली है। राजघाट, रेवला खानपुर, रोहिणी सेक्टर-37 और बुराड़ी में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो का संचालन यह कंपनी कर रही है। इसके लिए कंपनी को कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में इन 350 कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक बसों के नए डिपो में समायोजित किया जा सकता है।

वहीं डिम्ट्स मैनेजमेंट का कहना है कि सरकार से जल्द ही वार्ता होनी है। क्लस्टर बसों के संचालन के लिए सरकार की अन्य कंपनी से अनुबंध की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अगर सरकार बसों के संचालन की जिम्मेदारी कुछ महीनों के लिए और डिम्ट्स को देगी तो कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

इनसाइड

गृहणियों में बढ़ रहा है मेंटल स्ट्रेस, एक्सपर्ट्स ने बताया खुश रहने का तरीका

बाहर जा कर काम करने वाली महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मूड बदलने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है. ऐसे में वो घर में ही गुस्से में, द्वंद्व में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं.

पूरे घर को संभालने वाली (गृहणी/हाउसवाइफ) हमारी मां या पत्नी घर के हर एक सदस्य की जरूरत का ख्याल रखती हैं. उनका पूरा दिन घर की चार दीवारी में ही शुरू होता है और उसी में खत्म हो जाता है. सुबह से रात तक उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी भी सदस्य को घर में कई तकलीफ न हो. ये सब वो किसके लिए करतीं हैं? अपने परिवार के लिए, परिवार की खुशियों के लिए. फिर जब कभी वो जरा गुस्सा हो जाती हैं, तो हम उन्हें गलत समझने लगते हैं. लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो भी कितनी तरह के तनाव से जूझ रही है? उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात की है? ओनली माई हेल्थ की न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, बाहर जा कर काम करने वाली महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मूड बदलने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है. ऐसे में वो घर में ही गुस्से में, द्वंद्व में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं. इस रिपोर्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (Clinical Psychologist) डॉ. प्रज्ञा मलिका (Dr. Pragya Malika) का कहना है कि हाउसवाइफ में तनाव कई वजहों से होता है. ऐसी स्थिति में वे अकेले रहने लग जाती हैं. परिवार में जब कॉन्फ्लिक्ट्स (झगड़े और विवाद) बढ़ते हैं तो वे एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं. जब ये मुद्दे हल नहीं हो पाते तो सुसाइड, तलाक या अन्य मेंटल डिसऑर्डर (Mental Disorder) में बदल जाते हैं. इसे ही दुष्चक्र या विशियस साइकल (Vicious Cycle) कहते हैं. डॉ. प्रज्ञा के मुताबिक हाउसवाइफ इन तरीकों को अपनाकर खुश रह सकती हैं.

अपनी हॉबीज को करें याद

डॉ प्रज्ञा का कहना है कि अक्सर महिलाएं घर के काम में उलझकर अपनी हॉबीज (शौक) को भूल जाती हैं. जब ये निराशा या कुंठा बढ़ने लग जाए, तो अपने हुनर को याद करें. वो काम जिसे आप पूरे मजे के साथ करते थे, वो दोबारा करें. खुद सोचें कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है. ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

परेशानी का कारण ढूंढे

डॉ. प्रज्ञा के मुताबिक हाउसवाइफ को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें परेशानी किस बात से हो रही है. जब परेशानी की वजह मालूम हो जाए, तब उस पर काम करें. उस परेशानी को मैनेज करें. दरअसल, महिलाओं की टेंशन की एक वजह ये भी है कि महिला और पुरुष का दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है. जैसे महिलाएं इमोशनल होकर सोचती हैं और पुरुष लॉजिस्टिक तरीके से सोचते हैं.

नए दोस्त बनाएं

हाउसवाइफ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नए दोस्त बना सकती हैं. अपने घर के आसपास, रिश्तेदारों में या स्कूल-कॉलेज के दोस्तों के संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहना भी कई बार इस स्ट्रेस से निकलने में मदद करता है.

अपने लिए टाइम निकालें

एक हाउसवाइफ होने के नाते आप क्या चाहती हैं? हाउसवाइफ होने के नाते आपके कुछ सपने होते हैं. तो यहां उन्हें सोचने की जरूरत है कि आप क्या चाहती हैं. खुद को खुश रखने के लिए अपना मी टाइम निकालें.

कुछ चीजों को हालात पर छोड़ दें

डॉ. प्रज्ञा का कहना है कि जिस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकतीं. जो हालात आपके बस से बाहर हैं, तो उन पर न सोचें.

काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ रहा है वजन, महिलाएं फॉलो करें ये टिप्स, तेजी से होगा वेट गेन

कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाकर महिलाएं आसानी से वेट गेन कर सकती हैं

दुबली-पतली महिलाएं आमतौर पर वेट गेन करने के लिए अनगिनत नुस्खे आजमाती हैं, मगर हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कई बार वजन नहीं बढ़ पाता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन महिलाओं के लिए बेस्ट हो सकता है.

स्लिम एंड ट्रिम लुक कैरी करने के लिए महिलाएं कई तरीके अपनाती हैं. इसके बावजूद कुछ महिलाएं मोटापे का शिकार होने लगती हैं. तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं. अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इन चीजों को डाइट में शामिल करके आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं.
पतली और दुबली महिलाएं अक्सर अपने फिगर को लेकर टेंशन में रहती हैं. वहीं पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के बाद भी कई बार महिलाओं का वजन बढ़ने का नाम नहीं लेता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है. तो आइए ओन्लीमाईहेल्थ डॉट कॉम के अनुसार, जानते हैं वजन बढ़ाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके महिलाएं खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

प्रोटीन का सेवन करें

नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को बॉडी का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है. खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शुगर और फैट भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है, जिससे मसल्स बिल्डिंग में काफी मदद मिलती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है. ऐसे में आप पनीर, फुल क्रीम मिल्क, दही और दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल कर सकती हैं. साथ ही चिकन, अंडा, लाल मीट, मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर जैसी चीजों से आप आसानी से वेट गेन कर सकती हैं.

फैट रिच डाइट लें

वजन बढ़ाने के लिए महिलाएं फैट से भरपूर चीजों को भी डाइट में एड कर सकती हैं. ऐसे में घी, मक्खन, नट्स और गुड फैट से भरपूर चीजों का सेवन करना महिलाओं के लिए बेस्ट होता है. इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है और महिलाओं के वजन में भी इजाफा देखने को मिलने लगता है.

कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाएं

कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें बॉडी में कैलोरी इन टेक को बढ़ावा देती हैं. जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में वेट गेन करने के लिए महिलाएं आलू, शकरकंद, ओट्स, ग्रेन और ब्राउन राइस का सेवन कर सकती हैं. वहीं घी और बटर से युक्त चीजें खाने से भी वेट गेन फास्ट होने लगता है.

वजन ना बढ़ने के कारण

महिलाओं में वजन ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. दरअसल कई बार महिलाओं के शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हेल्दी डाइट लेने के बावजूद महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है और उनका वजन कम रहता है. इसके अलावा इंफ्लेमेटरी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और हाइपोथायरॉयडिजम के चलते भी महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता है.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हो जाती है इन विटामिंस की कमी

पुरुषों की तुलना में अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी12 जैसे जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है. अगर महिलाएं खुद की सेहत का ख्याल रखें तो प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान समस्याओं से बच सकती है. आइए जानते हैं कि किन विटामिन की कमी महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है.

अक्सर महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि रात भर सोने के बावजूद थकान महसूस करती हैं या उन्हें हर वक्त कमजोरी का अनुभव होता है. इन समस्याओं को वे लंबे समय तक नजरअंदाज करती जाती हैं जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है. अगर महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान रखें और शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की आपूर्ति के लिए हेल्दी डाइट लें तो जीवन भर हेल्दी जीवन जी सकती हैं.

वुमनहेल्थ के मुताबिक, दरअसल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता पड़ती है. हर विटामिन और मिनरल्स के अपने अलग फायदे हैं जो शरीर के अलग अलग कामों को पूरा करने में मदद करते हैं. लेकिन कई वजहों से महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कुछ खास तरह के विटामिन और खनिजों की कमी पाई जाती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को किन विटामिन की कमी हो जाती है और वे किस तरह इन्हें पूरा कर सकती हैं.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इन विटामिन्स की हो जाती है कमी

फॉलिक एसिड या विटामिन बी9

फॉलिक एसिड शरीर में ब्लड सेल्स बनाने और डीएनए क्रिएट करने का काम करता है. यह भ्रूण के बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से प्रीमेच्योर बर्थ या जन्म के समय कम वजन होने का खतरा हो सकता है. ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को रोजाना 400 से 800 एमसीजी फॉलिक एसिड डायटरी सेप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है. इसकी आपूर्ति के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज, नट्स, चिकन आदि का नियमित सेवन करें.

विटामिन बी12

विटामिन बी12 ब्लड सेल्स और ब्रेन न्यूरॉन बनाने का काम करता है. यह भी प्रेगनेंसी में जरूरी होता है. इसके अलावा जो महिलाएं शाकाहारी हैं और जिनकी उम्र 50 से अधिक है उन्हें विटामिन बी12 की कमी हो सकती है. इसके लिए आप मिल्क, अंडा, चीज, चिकन, लीवर आदि डाइट में शामिल कर सकती हैं.

विटामिन डी

शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी होता है. यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है. जबकि सूरज की रौशनी से स्किन का डायरेक्ट संपर्क ना होने की वजह से महिलाओं में विटामिन डी की काफी कमी पाई जाती है. इसके लिए आप सेप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं.

कैल्शियम

लड़कियों को ग्रोइंग एज में जहां 1300 एमजी कैल्शियम की जरूरत होती है, वहीं मेनोपॉज के बाद 1200 एमजी कैल्शियम की जरूरत होती है. लेकिन अधिकतर मामलों में महिलाओं में इसकी कमी पूरी नहीं हो पाती. इसके लिए आप कैल्शियम रिच फूड का सेवन करें और सेप्लीमेंट का सेवन करें.

आयरन

महिलाओं में आयरन की कमी की समस्या भी काफी आम है. जिस वजह से उनके शरीर में ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से ना हो पाने के कारण कमजोरी, चक्कर आना जैसी समस्या होने लगती है. ऐसे में आप आयरन रिच चीजों को डाइट में शामिल करें.

अपनी बेटियों को करें प्रोत्साहित आत्मविश्वास भरना बेहद आवश्यक

आप आप एक बेटी के माता-पिता हैं तो ये बिलकुल भी ना सोचें कि वो एक बेटी होने के नाते जीवनभर संघर्ष करेगी। आप उसकी किसी ताकत या कमजोरी की धारणा बिलकुल ना बनाएं। उसकी खूबियों को प्रोत्साहित करने के साथ उसकी कमजोरियों को भी समय पर पहचानें और उसे सुधारने की कोशिश करें।

कहते हैं कि बेटियां अपने माता-पिता के लिए बेहद ख़ास होती हैं। जितनी वो खास होती हैं उतनी ही ख़ास उनकी देखभाल भी होती है। जैसे-जैसे बेटियां बड़ी होती जाती हैं, वैसे-वैसे उनके प्रति माता-पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। बात अगर पुराने जमाने की करें तो पहले घर-परिवार में बेटियों के पैदा होने पर उन्हें शगुन और साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता था। लेकिन आज के समय में भी बेटियां अपने आत्मविश्वास से ऊंचे से ऊंचा आसमान छूने की प्रतिभा रखती हैं। आज के समय में उनका दर्जा लड़कों से कम नहीं है। ये सब कुछ उनके माता-पिता की परवरिश का नतीजा होता है, जिससे उनका सिर गर्व से ऊपर उठता है। बहुत से माता-पिता होते हैं जो अपने बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हर दिशा में आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। यदि आप के घर में भी बेटी है तो आज का ये लेख खास आपके लिए है, जिसके जरिये हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसकी सही तरीके से परवरिश करें जिससे वो आत्मविश्वास से भरी रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।

1. बेटी को करें प्रोत्साहित–जब बेटी बड़ी होती है, तो उसकी जरूरतें भी अल्फ होती चली जाती हैं। आप उसे जमीन से जुड़े रहना सिखाएं। अगर वो आगे बढ़ाने के लिए अपने भविष्य को लेकर कुछ चुनाव करती है तो उसे हताश ना करें। उसका साथ दें। एक बच्चे के लिए उसके माता-पिता का साथ बेहद जरूरी होता है। आप उसे प्रोत्साहित करें। ताकि उसके अंदर का आत्मविश्वास कम ना हो।

2. बेटी की करें तारीफ– आप अपनी बेटी को बताएं की वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। उकसे अंदर ऐसी बात है जो उसे बाकियों से जुदा बनाती है। इससे बिटिया का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा।

3. सीखने का दें अवसर–अगर बेटी को संगीत या किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्ट्रेस्ट हैं लेकिन वो इन में फिट नहीं बैठते। ऐसे में अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो उसका मनोबल टूटता चला जाएगा। उसे सीखने का अवसर जरुर दें। उसे अपनी असल प्रतिभा धीरे-धीरे खुद समझ आएगी और वो आगे बढ़ेगी।

4. बेटी को सिखाएं समाजिकता–बेटी को समाज और उससे जुड़ी बातों के बारे में सिखाएं। उसे सिखाएं कि अगर उससे कोई दोस्ती नहीं करता तो उसका क्या कारण हो सकता है। समाज के प्रति उसके अंदर नकारात्मकता ना भरें। वरना एक समय के बाद वो समाज को नकारात्मक नजरिये से देखने लगेगी। उसे सभी पहलुओं के बारे में जरुर सिखाएं।

5. बढाएं बेटी की क्षमता–अगर आपकी बेटी अपना होमवर्क कर रही है तो यूं ही उसकी मदद ना करें। वो जब तक आपसे मदद नहीं मांगती तब तक उसकी मदद मत करें। उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम करने दें। उसे अपने दम में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करें।

6.ना थोपें अपनी मर्जी– आज के समय में बेटियां स्पोर्ट्स को ज्यादा पसंद कर रही हैं, और उसी में अपना भविष्य भी तय कर रही हैं। अगर वो एक जिमनास्टिक बनना चाहती है या फुटबॉल खेलना चाहती है तो उसे आगे बढ़ने दें, ना की अपना फैसला या अपनी चाह उसपर थोपें। आप ये जरुर पता लगा सकते हैं, कि वो किस खेल को खेलने के लिए ज्यादा सक्षम है। आप खुद उसके लिए कोई खेल तय ना करें।

7. मत बनाइए कमजोर–आप आप एक बेटी के माता-पिता हैं तो ये बिलकुल भी ना सोचें कि वो एक बेटी होने के नाते जीवनभर संघर्ष करेगी। आप उसकी किसी ताकत या कमजोरी की धारणा बिलकुल ना बनाएं। उसकी खूबियों को प्रोत्साहित करने के साथ उसकी कमजोरियों को भी समय पर पहचानें और उसे सुधारने की कोशिश करें।

8. सेक्सिज्म के लिए करें तैयार–बहुत लोगों की सोच है कि बेटियां वो काम नहीं कर सकती जो बेटे कर सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी को वो टीवी शो या फ़िल्में देखते हुए नोटिस करते हैं जो पूरी गर्ल्स पर आधारित होती है तो उसे समझिये और उसे सेक्सिज्म के लिए तैयार करें।

9. बेटी को दिखाएं रोल मॉडल–अक्सर ऐसा होता है जब भी आप कोई न्यूज़ देखते या पढ़ते हैं तो उसमें आपको कई महिलाएं सीनेटरी, खिलाड़ी, चिकित्सक या एथलीट दिखेंगी। ये अच्छा तरीका होता है अपनी बेटी को इन महिलाओं के बारे में दिखाना और समझाना। आप इम्नें से कोई भी अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल चुनने में उसकी मदद कर सकते हैं।

तो ये कुछ ऐसी खास टिप्स हैं, जिनकी मदद से आप अपनी बिटिया को अच्छी परवरिश देने के साथ उसमें आत्मविश्वास भर सकते हैं। अगर आपकी भी बेटी है तो आप हमारी बताई हुई टिप्स को जरुर आजमाएं। आपको इससे बेहतर परिणाम मिलेगा।

विभव बेल याचिका खारिज कोर्ट में मालीवाल रो पड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट - बदसलूकी मामले में तीस हजारी कोर्ट में सोमवार को विभव को पेश किया गया। कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील जज को बताया कि स्वाति मालीवाल के संवेदनशील अंगो पर चोट के कोई निशान नहीं है।हो सकता है कि उन्होने खुद को ही चोटिल कर लिया ।

विभव कुमार के वकील की दलीलें सुनकर स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही फफक-फफक कर रो पडी। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पद से हटाए जाने के बावजूद विभव कुमार वहां मौजूद थे। जो कि साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ और थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोप है कि 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची स्वाति मालीवाल से विभव कुमार ने मारपीट के तहत लात घूसे, थप्पड मारे थे। स्वाति मालीवाल की ओर से एफआईआर कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और अभी भी वह न्थान्यायि हिरासत में है। दूसरी और .मालीवाल के मेडिकल रिपोर्ट मामले में सामने आया था कि उनके पैर और गाल पर चोटे लगी थी।मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए थे।फिलहाल अभी जांच जारी है। विभव की ओर से वकील हरी हरण पेश हुए। हरिहर ने सवाल उठाए क्या कोई

शख्स इस तरह से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस सकता है।विभव ने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसी सिलसिले में विभव कुमार को तीन दिन के रिमांड के बाद सोमवार को तीस हजारी जिला कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने 4 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया था कोर्ट ने 5:30 बजे बजे फैंसला सुना दिया। फैसले में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया , और जेल में भेज दिया।

अरविंद केजरीवाल के लिए गया दिल्ली हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता वकील को मांगनी पड़ी माफी; ये था मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वकील पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया। वकील ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता वकील ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वकील पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया। वकील ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता वकील ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। उसे दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के निर्देशों पर सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साथ ही वकील को निर्देश किया कि अगर वह आगे कभी कोई याचिका दायर करता है तो उसे लागत आदेश के साथ ही छूट आदेश की एक प्रति (कॉपी) भी देनी होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ता अपनी गलती स्वीकार करता है, इसलिए उस पर लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना माफ किया जाता है। उसे डीएसएलएसए के निर्देशों के अनुसार सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाता है। हाईकोर्ट ने 8 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग करने वाली वकील की जनहित याचिका को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था। वकील ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए कोई भी अनुचित दबाव डालने से रोकने की भी मांग की थी।

कार्यालय के लिए जमीन मांग रही आप, केंद्र सरकार ने कहा- नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट के पाले में गेंद, इस दिन आएगा फैसला

अपने कार्यालय के लिए अस्थायी आधार पर जमीन आवंटित करने की मांग का निर्देश देने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान आप ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत 15 जून तक उसे राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय को खाली करना है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अपने कार्यालय के लिए अस्थायी आधार पर जमीन आवंटित करने की मांग का निर्देश देने की मांग वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान आप ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत 15 जून तक उसे राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय को खाली करना है, ऐसे में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर उसे अस्थायी तौर पर आवंटन किया जाए।

वहीं, केंद्र सरकार ने आवंटन का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि मामले पर अदालत पांच जून को अपना निर्णय सुनाएगी। अदालत ने इसके साथ ही मामले को दस जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

'अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार आप'

आप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है। उन्होंने यह भी कहा कि आप सरकार के एक मंत्री दीन दयाल उपाध्याय स्थित अपने आवास को पार्टी के पक्ष में देने को तैयार हैं।

पार्टी दो-तीन महीने के लिए मांग रही जमीन

उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उक्त जगह आप के लिए आवंटित करने से केंद्र सरकार को हानि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आप स्थायी तौर पर आवंटन की मांग नहीं कर रही है, AAP सिर्फ दो या तीन महीने के लिए आवंटन की मांग कर रही है।

2014 में दी गई थी जमीन, लेकिन AAP ने...

वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि आवंटन सामान्य पूल से होना है और राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष सूची नहीं है। केंद्र ने कहा कि आप को वर्ष 2014 में अपने कार्यालयों के लिए जमीन की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसे में पूल से एक आवास इकाई आवंटित करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक डीडीयू मार्ग स्थित इकाई का सवाल है उसे सरकार को वापस करना होगा।

पिछली सुनवाई पर आप ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही है। जबकि, केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास डीडीयू मार्ग पर कोई जमीन खाली नहीं है।

15 जून को खाली करना है वर्तमान कार्यालय

सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार, आप को 15 जून तक डीडीयू मार्ग पर अपना वर्तमान कार्यालय खाली करना होगा, जो पारिवारिक अदालतों के लिए आवंटित है। अदालत मध्य दिल्ली में अपने कार्यालय के लिए अस्थायी आवंटन या स्थायी आवंटन की मांग वाली आम आदमी पार्टी की दो याचिकाओं पर विचार कर रही है।

दिल्ली में 49 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, ये इलाका रहा सबसे गर्म; जानिए गर्मी से कब बदल सकते हैं हालात

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी और गर्म हवाओं से लू हालात खराब हैं। पूरी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को तापमान 48 डिग्री पार कर गया है। गर्मी को लेकर ऐसी स्थिति अभी कई दिनों तक बनी रहने की संभावना है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी और गर्म हवाओं से लू हालात खराब हैं। पूरी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को तापमान 48 डिग्री पार कर गया है। गर्मी को लेकर ऐसी स्थिति अभी कई दिनों तक बनी रहने की संभावना है।

दिल्ली के मुंगेशपुर का इलाका सोमवार को सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, नजफगढ़ में 48.6, नरेला में 48.4, पीतमपुरा में 47.6, पूसा में 47.2 और जफरपुर में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के यह इलाके सबसे गर्म इलाके हैं। वहीं, मुंगेशपुर में रविवार को भी तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। वहीं, अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार कर गया। मौसम विभाग ने लू चलने और भीषण गर्मी रहे की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी।

घर से बाहर निकलना मुश्किल

मई महीने में गर्मी अपने चरम पर है। तेज गरम हवाएं और तेज धूप के चलते 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग और चिकित्सक भी इस समय घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं। अगर जरूरी है तो चेहरा ढककर निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं, खुद को ठंडा रखने के लिए पानी बार-बार पीने को कहा गया है।

कब बदलेंगे हालात

मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक गर्मी एवं भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हवा की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है। माह के अंतिम दिन यानी 31 मई को हल्की वर्षा की संभावना भी जताई गई है।

कब तक बनेगी एलजी गोलचक्कर से एक्सप्रेसवे लिंक रोड, डेडलाइन नहीं तय

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) क्षेत्र में आने वाली जमीन के विवाद के कारण किसानों से समझौता नहीं हो रहा था लेकिन करीब तीन महीने पहले ये समस्या भी सुलझ गई है। लेकिन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिख रही है। इस कारण परीचौक और एलजी गोलचक्कर पर व्यस्त समय के अलावा भी जाम की स्थिति रहती है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण की ओर से आठ वर्ष पहले एलजी गोलचक्कर से नालेज पार्क होते हुए हरनंदी के रास्ते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक रोड का निर्माण जल्द पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।

पूर्व में नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली जमीन के विवाद के कारण किसानों से समझौता नहीं हो रहा था, लेकिन करीब तीन महीने पहले ये समस्या भी सुलझ गई है। बावजूद इसके ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिख रही है। नॉलेज पार्क-तीन में पुश्ते के पास अब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका।

अगले साल होगा ऑटो एक्सपो का आयोजन

इस कारण परीचौक और एलजी गोलचक्कर पर व्यस्त समय के अलावा भी जाम की स्थिति रहती है। सितंबर में मोटो जीपी प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो होना है, अगले साल ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। इन तीनों ही आयोजन के दौरान वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा।

हर बार कि तरह जगह जगह रूट डायवर्ट किया जाएगा। लिंक रोड बनने से औद्योगिक सेक्टरों और आवासीय सेक्टरों में जाने वाले हजारों वाहनों को परी चौक पर नहीं आना पड़ेगा, जिसका सीधा असर परी चौक के जाम को करने पर पड़ेगा। ये हाल तब है कि जब कि प्राधिकरण की हर बोर्ड बैठकों में परी चौक के जाम की समस्या प्रमुख एजेंडा में होती है।

आठ वर्ष से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में काम नहीं शुरू

2015 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एलजी गोलचक्कर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक रोड की योजना बनाई थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हिस्से में जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन आठ वर्ष से नोएडा क्षेत्र के किसान अधिग्रहण की राशि पर सहमत नहीं थे।

इसी वर्ष मार्च में ये समस्या भी दूर हो गई। उधर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब खोदाई का काम शुरू किया है और जमीन को खाली कराया जा है। ये हाल तब है जब आठ वर्ष से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसी तरह की रुकावट नहीं थी। परियोजना कब तक पूरा होगी इसकी डेडलाइन तक तय नहीं की गई है।

नोएडा के हिस्से में निर्माण शुरू

उधरनोएडा की तरफ बन रही एप्रोच रोड हरनंदी पुल से नोएडा एक्सप्रेसवे की 45 मीटर सर्विस रोड तक करीब 623 मीटर लंबी होग। निर्माण कंपनी ने कार्य शुरू दिया है।

इस पूरे प्रोजेक्ट पर 147 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे है। नालेज पार्क से ये लिंक रोड करीब तीन किलोमीटर लंबा है। इसे 60 मीटर चौड़ा बनाया जाना। इस लिंक रोड पर एक पुल हरनंदी नदी पर सेतु निगम बनाएगा, जिसकी लागत करीब 62 करोड़ रुपये है।

लिंक रोड से ये होगा फायदा

दिल्ली से एक्सप्रेसवे होते हुए परीचौक होते हुए ग्रेटर नोएडा एलजी चौक, कलक्ट्रेट , सूरजपुर व गाजियाबाद को जाने वाले यातायात को 16 किमी अतिरिक्त चलना पड़ता था। इसके बनने से ऐसा नहीं होगा।

इस लिंक रोड बनने से नोएडा के सेक्टर-151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162 औद्योगिक सेक्टरों ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा, बीटा, सूरजपुर, साइट बी व सी औद्योगिक क्षेत्र, डेल्टा, पुलिस लाइन, ईकोटेक दो व तीन आदि को फायदा होगा।

भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट, सभी अस्पतालों को बेड रिजर्व रखने को कहा

भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पूर्वी दिल्ली के नवजात अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर बैठक की। इसके साथ-साथ भारद्वाज ने दिल्ली में चल रही लू को देखते हुए समीक्षा बैठख की। उन्होंने कहा गर्मी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 26 सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए प्रत्येक में दो बिस्तर आरक्षित रखेंगे जबकि एलएनजेपी अस्पताल में पांच बिस्तर आरक्षित होंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल हीटस्ट्रोक के मरीजों के लिए दो-दो बिस्तर आरक्षित रखेंगे। वहीं उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में पांच बिस्तर आरक्षित रखने के आदेश दिए।

भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पूर्वी दिल्ली के नवजात अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर बैठक की। इसके साथ-साथ भारद्वाज ने दिल्ली में चल रही लू को देखते हुए समीक्षा बैठख की। उन्होंने कहा, ₹गर्मी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 26 सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए प्रत्येक में दो बिस्तर आरक्षित रखेंगे, जबकि एलएनजेपी अस्पताल में पांच बिस्तर आरक्षित होंगे।

अगले तीन दिनों रेड अलर्ट

बता दें, दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रही है। यहां पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अत्यधिक तापमान के कारण दिल्ली-एनसीआर में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद ही लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। बादल छाने के साथ बारिश के भी आसार हैं।

मानव तस्करी के आरोप में यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार, नौकरी देने के नाम पर युवाओं को भेजता था विदेश

परिवहन विशेष न्यूज

मानव तस्करी के आरोप में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 ने यूट्यूबर बॉबी कटारिया को सोमवार शाम गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सोमवार सुबह ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गोपालगंज निवासी अरुण कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस मंगलवार सुबह बॉबी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। उस पर युवाओं को बरगलाने का आरोप है।

गुरुग्राम। देश के युवाओं को नौकरी के नाम पर दूसरे देश भेजकर उनसे धोखाधड़ी करने और मानव तस्करी के आरोप में क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 ने यूट्यूबर बॉबी कटारिया को सोमवार शाम गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सोमवार सुबह ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गोपालगंज निवासी अरुण कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस मंगलवार सुबह बॉबी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी।

फतेहपुर निवासी अरुण कुमार ने बजघेड़ा थाने में दी शिकायत में कहा कि वह और उनके दोस्त हापुड़ के धौलाना निवासी मनीष तोमर बेरोजगार थे। दोनों ने इंस्टाग्राम पर बॉबी कटारिया को देखा था। उसके यूट्यूब चैनल पर दूसरे देश में नौकरी लगवाने की बात पता चली। मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो बॉबी ने दोनों को सेक्टर 109 कान्सेंट वन मॉल स्थित कार्यालय में बुलाया।

अंकित शौकीन नाम के व्यक्ति के खाते मे ट्रांसफर

दस जनवरी को मनीष और एक फरवरी 2024 को अरुण कुमार बॉबी से मिले। अरुण को दुबई में नौकरी लगवाने की बात कह पहले दो हजार रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए। इसके बाद बॉबी के कहने पर एक लाख रुपये उसके खाते में तो एक लाख रुपये अंकित शौकीन नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किए। बॉबी ने एजेंट शौकीन के वॉट्सऐप से लाओस की टिकट भिजवाई। 28 मार्च को बॉबी के कहे अनुसार अरुण एयरपोर्ट पर 50 हजार रुपये डालर में ट्रांसफर कराकर लाओस की फ्लाइट में बैठ गए।

दोनों से मारपीट कर पासपोर्ट छीन लिए गए

बॉबी ने मनीष से भी करीब ढाई लाख रुपये लिए। अरुण और मनीष दोनों एक साथ लाओस गए। लाओस के एयरपोर्ट पर उन्हें अभी नाम का व्यक्ति मिला। उसने अपने आप को बॉबी का दोस्त और पाकिस्तानी एजेंट बताया। अगले दिन अभी उन्हें ट्रेन से नावतुई ले गया। यहां अंकित शौकीन व नितीश शर्मा मिले। दोनों एक बेनामी चीनी कंपनी में ले गए। कंपनी के अंदर दोनों से मारपीट कर पासपोर्ट छीन लिए गए। अमेरीकियों के साथ साइबर फ्राड करने के लिए मजबूर किया गया।

कटारिया को उसके कार्यालय से किया गिरफ्तार

यहां उन्हें पता चला कि उस कंपनी में पहले से ही करीब डेढ़ सौ भारतीय इसी तरह मानव तस्करी कर लाए गए हैं। इनमें महिलाएं भी थीं। कई लोगों को बॉबी ने ही नौकरी का झांसा देकर यहां भेजा था। अरुण व मनीष ने दो दिन तक काम किया। इसके बाद दोनों भागकर भारतीय दूतावास पहुंचे। यहां मदद लेकर दोनों भारत वापस आ गए। शिकायत के बाद सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए बॉबी कटारिया को शाम को उसके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने ही उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। रिमांड के दौरान पूछताछ में कई और मामलों का पर्दाफाश हो सकता है।

बॉबी कटारिया का विवादों से रहा है नाता

13 अगस्त 2022 को बॉबी कटारिया का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें वह स्पाइसजेट में सिगरेट पीते नजर आ रहा था। स्पाइस जेट की ओर से आइजीआइ एयरपोर्ट के पुलिस थाने में बॉबी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

11 सितंबर 2022 को सड़क पर सरेआम ट्रैफिक रुकवाकर शराब पीने और पुलिस के साथ अभद्रता करने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में वह सड़क के बीचोंबीच टेबल लगाकर शराब पीता दिख रहा था। यह वीडियो देहरादून के कैंट कोतवाली क्षेत्र के किमाड़ी रोड का था। वीडियो में बॉबी शराब पीने के बाद खतरनाक तरीके से बुलेट चलाता भी दिख रहा था। देहरादून पुलिस ने इस वीडियो के बाद केस दर्ज कर उसके घर पर संपत्ति कुर्की का नोटिस भी लगाया था और 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था।

वहीं छह साल पहले बॉबी कटारिया को गुरुग्राम पुलिस ने रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य आरोप में गिरफ्तार किया था।

प्लॉट बेचने को जीडीए वीसी ने बनाया एक्शन प्लान, कोष में आएंगे 200 करोड़

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग प्लॉट जो काफी समय से नहीं बिक पा रहे हैं। उन्हें बेचने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इससे जीडीए के खाते में 200 करोड़ रुपये आएंगे। कई बार नीलामी में लगाने के बावजूद इन ग्रुप हाउसिंग भूखंडों को खरीदने के लिए किसी ने रुझान नहीं दिखाया। इसका कारण जानने के लिए बातचीत की गई है।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम योजना में श्मशान घाट के पास 20 हजार वर्ग मीटर जमीन पर सृजित ग्रुप हाउसिंग भूखंड जो काफी समय से नहीं बिक पा रहे हैं। इन्हें बेचने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष (वीसी) अतुल वत्स ने नया एक्शन प्लान बनाया है। इससे जीडीए के कोष में 200 करोड़ का इजाफा होगा और शहर की विकास रफ्तार को गति देने में मदद मिलेगी।

दरअसल, इंदिरापुरम स्थित ग्रुप हाउसिंग के भूखंड श्मशान घाट के पास होने के कारण बिल्डर इन्हें नहीं खरीद रहे हैं। कई बार नीलामी में लगाने के बावजूद इन ग्रुप हाउसिंग भूखंडों को खरीदने के लिए किसी ने रुझान नहीं दिखाया।

कारण जानने के लिए बातचीत के दौरान पता चला कि अगर यहां फ्लैट बनते हैं तो हाईराइज फ्लैटों की बालकनी से श्मशान घाट दिखेगा, इसी कारण खरीदार न मिलने के कारण बिल्डर इन भूखंडों को खरीदकर बहुमंजिला इमारत बनाने से बच रहे हैं।

काटे जाएंगे छोटे-छोटे आवासीय प्लॉट

जीडीए वीसी अतुल वत्स ने इन्हें बेचने का जो एक्शन प्लान बनाया है। उसके तहत सबसे पहले श्मशान घाट के चारों तरफ 15 मीटर ऊंची बाउंड्री बनाकर वर्टिकल गार्डेनिंग कराई जाएगा। इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों के स्थान पर उपरोक्त जमीन पर 100-200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के छोटे-छोटे आवासीय भूखंडों का सृजन कराया जाएगा।

श्मशान घाट की ऊंची बाउंड्री कराने के साथ वर्टिकल गार्डेनिंग कराने से छोटे आवासीय भूखंडों को खरीदने वाले लोगों को बालकनी से वर्टिकल गार्डेनिंग का आकर्षक नजारा दिखेगा। उपरोक्त 20 हजार वर्गमीटर भूमि पर छोटे आवासीय भूखंडों का सृजन करने से करीब 40 प्रतिशत भूमि सड़क व ग्रीन बेल्ट विकसित करने में इस्तेमाल की जाएगी।

अभी क्या है प्रति वर्गमीटर मार्केट रेट?

इसके बाद जीडीए को करीब 12 हजार वर्गमीटर भूमि भूखंड के रूप में बेचने के लिए मिलेगी। इन भूखंडों को जीडीए चुनाव आचार संहिता हटने के बाद नीलामी में बेचेगा। वर्तमान में क्षेत्र में 1.25 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से लेकर 1.50-1.60 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर का मार्केट रेट हैं। इस तरह मार्केट रेट के हिसाब से उस क्षेत्र में छोटे आवासीय भूखंड बेचकर जीडीए के कोष में करीब 200 करोड़ का इजाफा होगा।

रवि काना और काजल की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- बेल के लिए पर्याप्त आधार नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

काजल झा की जमानत याचिका सोमवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। एडीजीसी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से रवि और काजल की जमानत याचिका जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इन याचिकाओं का शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। इससे पहले 24 मई को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रवि काना की याचिका पर सुनवाई हुई थी।

नोएडा। स्क्रैप व सरिया माफिया रवि काना व उसकी महिला मित्र काजल झा की जमानत याचिका सोमवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। दोनों ने गैंगस्टर एक्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय ने माना की जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

एडीजीसी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से रवि और काजल की जमानत याचिका जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इन याचिकाओं का शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। इससे पहले 24 मई को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रवि काना की याचिका पर सुनवाई हुई थी।

जमानत याचिका स्वीकृत करने से इनकार कर दिया

पीड़ित युवती के बयान के आधार पर न्यायालय ने उस मामले में भी जमानत याचिका स्वीकृत करने से इनकार कर दिया था। सोमवार को गैंगस्टर मामले में रवि काना व काजल झा की ओर से जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। पुलिस की और से मजबूती से पैरवी की गई। रवि काना सहित उसके गिरोह के 16 लोगों के खिलाफ थाना बीटा-2 में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है।

रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित कारागार में बंद

गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह की 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। रवि काना को एक बार और काजल झा को पुलिस दो बार रिमांड पर भी ले चुकी है। थाईलैंड के बैंकाक से गिरफ्तार किए जाने के बाद रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित जिला कारागार में बंद है।

गाजियाबाद में कागजी दावों से 'कोसो' दूर है पानी की हकीकत, 20 प्रतिशत आबादी तक नहीं पहुंची गंगाजल लाइन

परिवहन विशेष न्यूज

गर्मी शुरू होने से पहले हर वर्ष पानी उपलब्ध कराने के यंत्रों को दुरुस्त किया जाता है। इस बार निगम ने यंत्रों को दुरुस्त कराने में लापरवाही बरती है। भीषण गर्मी में पानी की मांग बढ़ गई है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 20 प्रतिशत आबादी तक पेयजल लाइन नहीं पहुंची है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र में मांग के अनुसार पानी की आपूर्ति का दावा फेल हो रहा है। शहर में 450 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) से अधिक पानी की मांग है। जबकि कागजों में पानी की मांग 355 एमएलडी है।

निगम द्वारा 325 एमएलडी पानी की आपूर्ति का दावा किया जा रहा रहा है। इन दावों के बीच शहर में पानी की मारामारी है। 20 प्रतिशत आबादी तक निगम की गंगाजल लाइन नहीं पहुंची है। निगम की नाकामी के कारण पानी के पानी के प्लांट वाले चांदी काट रहे हैं।

भीषण गर्मी में बढ़ी पानी की मांग

गर्मी शुरू होने से पहले हर वर्ष पानी उपलब्ध कराने के यंत्रों को दुरुस्त किया जाता है। इस बार निगम ने यंत्रों को दुरुस्त कराने में लापरवाही बरती है। भीषण गर्मी में पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे में प्रतिदिन लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

पानी खरीदना पड़ रहा है। एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी की प्रतिदिन जरूरत होती है। निगम क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार मांग इससे कही अधिक है। निगम द्वारा 325 एमएलडी पानी की आपूर्ति करने का जो दावा कर रहे हैं वह दावा हकीकत से कहीं दूर है।

यह है गंगाजल की हकीकत

जलकल विभाग द्वारा 55 एमएलडी गंगाजल पानी की आपूर्ति करने का दावा किया जाता है। नलकूप के पानी में गंगाजल मिलाकर सुबह शाम एक-एक घंटे पानी देने की बात कही जाती है। गंगाजल की आपूर्ति शहर में वसुंधरा, वैशाली, डेल्टा कॉलोनी, कौशांबी, इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार में होती है। एक घंटे की बजाय 30 से 45 मिनट गंगाजल दिया जाता है। यह पानी पर्याप्त नहीं है।

20 प्रतिशत आबादी को पेयजल लाइन बिछने का इंतजार

नगर निगम क्षेत्र में 20 प्रतिशत आबादी तक पेयजल लाइन नहीं पहुंची है। इन लोगों को निगम की ओर से एक बूंद पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हालांकि निगम द्वार टैंकर से पानी की आपूर्ति का दावा किया जाता है। 20 प्रतिशत आबादी सबमर्सिबल के पानी पर निर्भर है। उन्हें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है।

एक वर्ष में हुए 66 बोरिंग फेल

घटते भूजल स्तर की वजह से एक वर्ष में 66 बोरिंग फेल हो चुके हैं। नगर निगम को इन बोरिंग को रिबोर कराना पड़ रहा है। कई बोरिंग अब भी रिबोर नहीं हुए हैं। निगम एक वर्ष में 15 नए बोरिंग किए हैं। वहीं मोहन नगर जोन में तीन रेनिवेल से भी पानी की आपूर्ति की जा रही है। इनका संचालन जल निगम कर रहा है।

निर्णायक क्षण- एक गलती से सदियों को सजा मिलेगी

तरुण विजया

देश सिर्फ पानी बिजली और सडकों से नहीं बनता। राष्ट्र की आत्मा और चैतन्य होता है। उस चैतन्य को जागृत होते हम देख रहें हैं तो विदेशी शक्तियां बौखला गयीं हैं। हर कीमत पर वे इस चैतन्य यात्रा को रोकना चाहते हैं- स्वार्थी विकृत सोच के भारतीयों की ही मदद से।

सही और गलत के मध्य बारीक धागे सा अंतर होता है लेकिन एक सही निर्णय राष्ट्र का निर्माण तो उसी गलत फैसला उस देश के लोगों को सदियों तक सजा देता है।

ग़ज़नवी हज़ार मील से भारत आया, सोमनाथ तोड़कर हज़ारों को गुलाम बनाकर हमारी धरती से ले गया- सही निर्णय होता कि सब भेद स्वार्थ भूलकर उसको रोकते, ख़त्म कर देते। ऐसा नहीं हुआ, शताब्दियों तक भारत को दुःख और दासता झेलनी पडी।

पानीपत में एक निर्णय गलत हुआ- आपसी समझ और भोजन की जिम्मेदारी के अहंकार ने जीती बाजी हरवा दी।

1947 में सत्ताकामी नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने विभाजन का गलत निर्णय लिया, दस लाख हिन्दू सिखों का नरसंहार हुआ, उसके बाद आज तक हम युद्ध की निरंतर विभीषिका झेल रहें हैं।

पटेल की जगह नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का गलत निर्णय हुआ, देश ने तुरंत एक लाख पचीस हज़ार वर्ग किलोमीटर भूमि के हाथों खोयी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सेना के स्थान पर केंद्रीय आरक्षी पुलिस की गश्ते लगवाईं। अक्साई चीन खोया। आज उसका दंश और निरंतर युद्ध हम झेल रहे हैं।

चुनाव भी केवल कुछ जाने अनजाने, अच्छे या कम अच्छे लोगों को लोकसभा भेजने का उपक्रम नहीं- यह राष्ट्र रक्षा के निमित्त युद्ध ही होता है जिसमें शताब्दियों भविष्य दांव पर लगा होता है। सही शासक राष्ट्र का नवीन निर्माण करते हैं- यदि विदेशी धन और मन वाले क्षुद्र विवेकी गए तो अच्छा खासा साम्राज्य ढहते देर नहीं लगती।

देश रक्षा के निर्णायक क्षणों में भी बहुत से लोग कहते देखे गए- मोदी तो ठीक है लेकिन जिनको टिकट दिया गया उनमें बहुत से निकम्मे और संवेदनहीन हैं, या सारे कांग्रेसी भर दिए- अब हम किसको पहचाने? वे भूल जाते हैं की युद्ध के समय सेनापति के निर्णय पर बहस नहीं हो सकती- सिर्फ सेनापति को देखो, हर सैनिक में सेनापति की छवि देखो, देश विजयी बनाने के लिए कटिबद्ध होकर

जूझो और विजयी होकर निकलो- बस यही एक लक्ष्य होता है।

ग़ज़नवी और गोरी हमारे अपने उन पूर्वजों की कमजोरियों और इन्ही स्वार्थों के कारण आए और हमें लूट गए जो कहते थे, हमारा क्या, हम अपनी जमींदारी, अपने हित संभाल रहे हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज तीस करोड़ भारतीयों पर ढाई सौ वर्ष राज कर गए- इन्ही स्वार्थी कूप मंडूक भारतीयों की सहायता से। इन्हीं भारतीयों ने अपने ही भारतीयों पर विदेशी शासकों के आदेश से जलियांवाला में गोलियां चलाईं और सावरकर जैसे हज़ारों क्रांतिकारियों पर अत्याचार किये। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी देने के फैसले पर पाखंडी मुहर लगाने के लिए लाहौर के अंग्रेज जज को स्थानीय गवाहियां चाहिए थीं- तीन सौ सिख मुस्लिम और सनातनी हिन्दुओं ने गवाहियां दीं- वे सब भारतीय थे। उनके नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार में फाइलों में हैं। सिर्फ राय साहबियत, राय बहादुरी खिताब लेने, साउथ नार्थ ब्लॉक बनाने की ठेकेदारी लेने हमने अपने देश के खिलाफ खड़े होने में लज्जा महसूस नहीं की। मुझे क्या मिलेगा? इसी प्रश्न पर हम देश की सदियों को ग़ुलामी और विनाश के अँधेरे में झोंक देने में संकोच नहीं करते।

देश सिर्फ पानी बिजली और सडकों से नहीं बनता। राष्ट्र की आत्मा और चैतन्य होता है। उस चैतन्य को जागृत होते हम देख रहें हैं तो विदेशी शक्तियां बौखला गयीं हैं। हर कीमत पर वे इस चैतन्य यात्रा को रोकना चाहते हैं- स्वार्थी विकृत सोच के भारतीयों की ही मदद से।

पराक्रमी और विजय की ओर उन्मुख नेतृत्व राष्ट्र निर्माण करता है, मुफ्त पानी, बिजली और लैपटॉप नहीं देता। बलिदानी सैनिकों की स्मृति यदि नागरिकों को सशक्त नेतृत्व निर्माण हेतु प्रेरित नहीं उनको राष्ट्र की किसी भी कल्याण योजना का लाभ उठाने का भी अधिकार नहीं हो सकता।

क्या आज का भारत, अपने राष्ट्र के मूल स्वभाव और सभ्यता की रक्षा करने वालों के साथ पराक्रम दिखते हुए खड़ा होगा या ग़ज़नवी को रास्ता देने वालों की तरह केवल अपने लिए मुफ्त बिजली पानी मिलने तक सीमित रहेगा?

पिछले वर्षों में खालिस्तान का आतंकवाद, कश्मीर से कोयंबटूर तक के जिहादी विस्फोट, हिन्दुओं का हर कदम पर अपमान, हर वर्ष होने वाले दंगे, पाकिस्तानी आतंकवाद, गरीबी का फैलाव, सडकों की जगह गड्ढे। राशन की तरह खुशामद कर करके गैस के सिलिंडर लेने की कवायद, कठिन और बेतरतीब रेल यात्रायें, विदेशों में हमारे प्रति एक तिरस्कार और गरीब-पिछड़े- सबसे भ्रष्ट देश होने की दृष्टि से भारतीयों की ओर देखने वाले विदेशी- क्या यह सब हम भूल गए और इसमें हुआ विराट परिवर्तन हममें कोई उत्साह और जोश पैदा नहीं करता?

पांच सौ वर्ष तक चले संघर्ष के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाले हिन्दुओं ने अपनी पत्रिकाओं में वहां शौचालय बनाने के सुझाव दिए- इस मानसिकता को पराभूत किसने किया? किसने हिन्दू गौरव की पुनःस्थापना की? किसने कहा कश्मीर में एक भी सांप और जिहादी चोर को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे? संघ के स्वयंसेवक और तपस्वी प्रचारक दीखते नहीं लेकिन देश बदल देते हैं। वे हज़ारों गैर काषाय वस्त्र धारी प्रचारक जिन्होंने मां से घर छोड़ते समय आशीर्वाद लेते हुए सिर्फ यही कहा था- भारत माता विजयी हो केवल यही अब जीवन का व्रत है- उनके तप के रंग के खिलने का समय यही है जब भारी मतदान द्वारा राष्ट्र घातक तत्वों को पराभूत करने का दम ख़म दिखाया जाये।

उन्ही प्रचारकों में से एक नरेंद्र मोदी ने देश बदला, साहसिक निर्णय लिए और अब आधारभूत ऐसे परिवर्तन करने का समय है जिनसे आगामी सदियों का भारत सदैव के लिए शक्ति पथ पर चलेगा। यह नवीन भारत के लिए एक ऐतिहासिक निर्णायक क्षण है। कभी किसी को ऐसा लिखना न पड़े कि- लम्हों ने खता की थी- सदियों ने सजा पायी।

BYD ने शुरू की लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान कार सील की डिलीवरी, जानें कैसे हैं फीचर्स और कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD की ओर से भारतीय बाजार में लग्जरी वाहनों की बिक्री की जाती है। कंपनी ने हाल में ही Electric Sedan car Seal की डिलीवरी को शुरू कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इस कार में किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD ने भारतीय बाजार में अपनी पहली Electric Sedan Car Seal की डिलीवरी को शुरू कर दिया है। कंपनी ने पहले दिन कितनी यूनिट्स की डिलीवरी की है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है और इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में इसकी जानकारी दे रहे हैं।

शुरू हुई BYD Seal की डिलीवरी

बीवाईडी की ओर से Electric Sedan Car के तौर पर Seal को ऑफर किया जाता है। कंपनी ने 26 मई 2024 से ही इस लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान कार की डिलीवरी को शुरू किया है। भारत में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि सहित कई शहरों में इस कार के ग्राहकों को डिलीवरी दी गई है।

March 2024 में हुई थी लॉन्च

बीवाईडी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक सेडान कार को March 2024 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इस कार को कंपनी की ओर से साल 2023 में हुए ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया गया था। लॉन्च के बाद से ही इसके लिए कंपनी को एक हजार से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं।

अधिकारियों ने कही यह बात

बीवाईडी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट संजय गोपालकृष्णन ने कहा कि भारत में BYD SEAL का मजबूत स्वागत प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को रेखांकित करता है जो प्रदर्शन, स्थिरता, शैली और मूल्य का सहज मिश्रण पेश करते हैं। हमें विश्वास है कि BYD SEAL भारत के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे ग्राहकों को BYD SEAL का राष्ट्रव्यापी हस्तांतरण एक साथ हमारे मूल्यवान ग्राहकों और डीलरशिप नेटवर्क के साथ इस मील के पत्थर का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है जो टिकाऊ गतिशीलता के लिए हमारे दृष्टिकोण को साझा करते हैं।

कैसे हैं फीचर्स

बीवाईडी की ओर से भारतीय बाजार में पेश की जाने वाली Seal लग्जरी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेडान कार में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया है। इसमें Level-2 ADAS, NFC कार्ड इंटीग्रेशन, नौ एयरबैग, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हीटेड और वेंटिलेटिड फ्रंट सीट्स, 15.6 इंच टचस्क्रीन, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर

बीवाईडी सील में सेल टू बॉडी तकनीक का उपयोग करती है। इसमें सिंगल और ड्यूल मोटर का विकल्प दिया जाता है। इसके डायनैमिक वेरिएंट को 201 बीएचपी और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ लाया जाता है। वहीं इसके प्रीमियम वेरिएंट में लगी मोटर से इसे 308 बीएचपी और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें लगी मोटर से कार को सिर्फ 3.8 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें लगी बैटरी को चार्ज करने के बाद 650 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है।

कितनी है कीमत

कंपनी की ओर से इस इलेक्ट्रिक सेडान कार की एक्स शोरूम कीमत की शुरूआत 41 लाख रुपये से होती है। इस कीमत पर इसके डायनैमिक वेरिएंट को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इसके प्रीमियम वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 45.55 लाख रुपये और परफॉर्मेंस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 53 लाख रुपये तय की गई है।

किआ जल्द ला सकती है तीन इलेक्ट्रिक SUVs, जानें लिस्ट में कौन कौन सी EV शामिल

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia Motors भारत में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को ऑफर करती है। कंपनी की ओर से जल्द ही तीन Electric SUVs को देश में पेश करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Kia की ओर से किस किस सेगमेंट में कौन सी Elecrtic EV को लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में लगातार Electric Cars और Suvs की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कंपनियों की ओर से भी कई मॉडल्स को भारत में पेश और लॉन्च किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Kia की ओर कब तक और किस सेगमेंट में किस EV SUV को लाया जा सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

Kia EV9

Kia की ओर से फ्लैगशिप Electric SUV के तौर पर EV9 को पेश किया जाएगा। कंपनी की ओर से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को जनवरी 2023 में ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सिंगल चार्ज में करीब 500 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसके साथ ही इसे तीन रो सीट्स के साथ लाया जा सकता है। कंपनी इस EV को भारत में बनाने की जगह आयात कर सकती है।

Kia Carens

बजट एमपीवी सेगमेंट में Kia की ओर से Carens को ऑफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस एमपीवी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाएगी। हाल में ही इसके फेसलिफ्ट वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। जिसके साथ ही इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि इसके आईसीई वर्जन के फेसलिफ्ट के साथ ही EV वर्जन को भी भारत में पेश किया जा सकता है।

Kia Clavis SUV

EV सेगमेंट में किआ की ओर से Kia Clavis को पेश करने की तैयी हो रही है। सब फोर मीटर सेगमेंट वाली इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान कई बार साउथ कोरिया के साथ ही भारत में भी देखा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इसे इलेक्ट्रिक और आईसीई वर्जन में भी लाएगी। कंपनी की ओर से कुछ समय पहले ही Syros नाम को ट्रेडमार्क करवाया गया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Clavis को भारत में Syros के नाम से लाया जा सकता है।

Kia EV3

किआ ने हाल में ही EV3 को ग्लोबल बाजार में पेश किया है। जिसे EV9 से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। इस एसयूवी को कंपनी जुलाई में साउथ कोरिया में लॉन्च करेगी। इसके बाद यूरोप और साल के आखिर या अगले साल की शुरूआत में इसे भारतीय बाजार में भी पेश किया जा सकता है।

टाटा अल्ट्रोज रेसर ऑफिशियली टीज, जून में लॉन्च होने की उम्मीद; जानें क्या हो सकती हैं खूबियां

टाटा मोटर्स के द्वारा साझा किए टीजर से पुष्टि होती है कि अल्ट्रोज रेसर यूनीक ऑरेंज और ब्लैक डुअल टोन एक्सटीरियर फिनिश के साथ आएगी। ब्लैक ट्रिम रूफ विंग मिरर और विंडो लाइन तक सीमित नहीं होगा। इसमें अलॉय व्हील मौजूदा अल्ट्रोज की तरह ही दिखाई देते हैं। इस गाड़ी के जून में लॉन्च होने की उम्मीद है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज रेसर के लिए एक टीजर जारी किया है, जिसे अगले महीने लॉन्च किया जाना है। टाटा की प्रीमियम हैचबैक के इस स्पोर्टियर वेरिएंट में अल्ट्रोज की तुलना में अधिक शक्तिशाली इंजन, बदला हुआ एक्सटीरियर डिजाइन मिलेगा। आइए इस गाड़ी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या खास मिल सकता है।

Tata Altroz Racer हुई टीज

टाटा मोटर्स के द्वारा साझा किए टीजर से पुष्टि होती है कि अल्ट्रोज रेसर यूनीक ऑरेंज और ब्लैक डुअल टोन एक्सटीरियर फिनिश के साथ आएगी। ब्लैक ट्रिम रूफ विंग मिरर और विंडो लाइन तक सीमित नहीं होगा। इसमें अलॉय व्हील मौजूदा अल्ट्रोज की तरह ही दिखाई देते हैं।

कुछ दिन पहले टाटा अल्ट्रोज रेसर के स्पाई शॉट्स सामने थे, जिनसे पता चला कि अल्ट्रोज रेसर को बोनट पर सफेद रेसिंग लाइन्स मिलेंगी। मॉडल में रेसर बैज और थोड़ा बदली हुई ग्रिल होने की भी उम्मीद है।

इंटीरियर में क्या होंगे बदलाव

अल्ट्रोज रेसर के केबिन में बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। इसमें कॉस्मेटिक रूप से कंपनी कई बदलाव कर सकती है। इनमें डैशबोर्ड पर हाइलाइट्स और नई अपहोल्स्ट्री शामिल है। टाटा द्वारा रेसर को मानक अल्ट्रोज की तुलना में अधिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें नया 10.25-इंच टचस्क्रीन, एसी वेन्टीलेटेड सीट, 360-डिग्री कैमरा, एक हेड-अप डिस्प्ले और एक वॉयस-असिस्टेड सनरूफ हो सकता है।

Tata Altroz Racer इंजन ऑप्शन

इस गाड़ी के इंजन के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इसमें मौजूदा अल्ट्रोज iTurbo के

110hp, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की बजाय नेक्सॉन की 120hp शक्ति वाले 1.2-लीटर इंजन को दिया जा सकता है। गाड़ी लॉन्च होने के बाद हुंडई की i20 N लाइन को सीधे तौर पर टक्कर देगी। i20 N लाइन का इंजन 120hp की शक्ति और 172Nm का टॉर्क पैदा करता है। उम्मीद है कि टाटा रेसर को सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल फॉर्म में ही पेश किया जाएगा।

BMW से लेकर Audi तक, ये कंपनियां इस साल लॉन्च करेंगी पांच लग्जरी कारें, जानें कैसे होंगे फीचर्स

भारतीय बाजार में सामान्य कारों के साथ ही लग्जरी कारों की भी काफी ज्यादा मांग रहती है। इसी को देखते हुए BMW AUDI और मर्सिडीज बेंजकी ओर से कई लक्ज़री कार्स को इस साल तक भारत में पेश और लॉन्च किया जा सकता है। किस कंपनी की ओर से किस कार (अपकमिंग लक्ज़री कार्स) को लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई कंपनियों की ओर से लग्जरी कारों को ऑफर किया जाता है। इनमें Mercedes Benz, Audi, BMW, Volvo जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल में कुछ कंपनियों की ओर से पांच लग्जरी कारों को लॉन्च किया जा सकता है। किस कंपनी की ओर से किस कार को लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mercedes Benz New E Class

जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज की ओर से भारतीय बाजार में E Class को लंबे समय से पेश किया जाता है। लेकिन कंपनी की ओर से जल्द ही इसके नए वर्जन को पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इसे सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट में लाया जा सकता है। जिसमें दो लीटर का चार सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। इसके अलावा इसमें दो लीटर की क्षमता का डीजल इंजन भी दिया जा सकता है। मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले नया वर्जन 15 एमएम लंबा, 20 एमएम चौड़ा होगा।

BMW 5 Series

मर्सिडीज के अलावा दूसरी जर्मन कंपनी BMW भी भारत में नई 5 Series को लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस साल फेस्टिव सीजन की शुरूआत से पहले कंपनी की ओर से आठवीं जेनरेशन 5 Series को लाया जा सकता है।

Audi Q8 Facelift

तीसरी जर्मन कंपनी ऑडी भी अपनी Q8 के फेसलिफ्ट को इस साल भारत ला सकती है। कंपनी ने इस एसयूवी को पिछले साल सितंबर में ही ग्लोबल स्तर पर पेश किया था। एसयूवी में अपडेट के बाद कई नए फीचर्स दिए जाएंगे साथ ही इसके डिजाइन में भी हल्का बदलाव होगा। कंपनी इसे आयात करेगी और इसमें मौजूदा वर्जन वाला ही इंजन दिया जा सकता है।

Mini Countryman

बीएमडब्ल्यू की ईकाई Mini की ओर से भारत में जल्द ही Countryman को लाने की तैयारी की जा रही है। सितंबर 2023 में इसका ग्लोबल डेब्यू किया गया था। लेकिन अब इसे भारत में लाया जा सकता है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई जेनरेशन वाली कंट्रीमैन ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसके साथ ही इसे आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लाया जा सकता है। इसमें हेडलाइट, बंपर, केबिन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

Mercedes Benz Maybech EQS

मर्सिडीज की ओर से E Class के अलावा मेबैक ईक्यूएस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भी भारत लाने की तैयारी हो रही है। कंपनी इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में 108.4 kWh की क्षमता की बैटरी दे सकती है। जिसके साथ दो बैटरी दी जाएंगी। जिससे इसे 658 हॉर्स पावर और 950 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। इसकी अनुमानित रेंज 600 किलोमीटर तक होगी। एसयूवी होने के बाद भी यह सिर्फ 4.4 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जा सकेगी। इसकी अनुमानित कीमत चार करोड़ रुपये के आस-पास हो सकती है।

महिंद्रा XUV 3XO की पहले दिन हुई 1500 से ज्यादा डिलीवरी, जानें कैसी है खासियत और कीमत

भारतीय बाजार में Mahindra की ओर से 29 April को XUV 3XO को लॉन्च किया गया था। जिसके बाद इसकी डिलीवरी को 26 May 2024 से शुरू किया गया है। पहले ही दिन कंपनी ने इसकी 1500 से ज्यादा यूनिट्स को डिलीवर किया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में किस तरह की खासियत दी गई हैं इसकी कीमत क्या है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। महिंद्रा की ओर से अप्रैल महीने में ही XUV 3XO को लॉन्च किया गया था। जिसके बाद इसकी डिलीवरी की शुरूआत 26 मई से की गई है। कंपनी की ओर से पहले ही दिन एसयूवी की 1500 यूनिट डिलीवर की हैं। एसयूवी में किस तरह के फीचर्स, इंजन को दिया गया है। इसके कितने वेरिएंट बाजार में उतारे गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहले दिन हुई रिकॉर्ड डिलीवरी

महिंद्रा ने अपनी सबसे नई एसयूवी XUV 3XO की डिलीवरी को शुरू कर दिया है। कंपनी ने पहले दिन 1500 से ज्यादा यूनिट्स को देशभर में डिलीवर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग ने बेंगलुरू में तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन ने चेन्नई में ग्राहकों को एसयूवी की चाबी सौंपी। इसके अलावा देशभर के सभी शहरों में एसयूवी की डिलीवरी दी गई हैं।

कितनी हुई बुकिंग

कंपनी ने 15 मई से इसके लिए बुकिंग को शुरू किया था और सिर्फ एक घंटे में ही इसके लिए देशभर से 50 हजार से ज्यादा बुकिंग हो गई थीं। महिंद्रा ने XUV 3XO को 29 April 2024 को ही लॉन्च किया था।

कितनी होगी वेटिंग

महिंद्रा की ओर से जानकारी दी गई है कि कंपनी XUV 3XO की 10 हजार यूनिट्स का प्रोडक्शन किया हुआ है। इसके अलावा इस एसयूवी की हर महीने नौ हजार यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जिससे ग्राहकों को जल्द से जल्द एसयूवी की डिलीवरी की जाए। ऐसे में जिन ग्राहकों ने एसयूवी को पहले बुक किया है, उनको 26 मई से डिलीवरी देना शुरू कर दिया गया है। ज्यादा बुकिंग और सीमित प्रोडक्शन के कारण ग्राहकों को एसयूवी की डिलीवरी के लिए अधिकतम पांच से छह महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

नई सरकार की प्राथमिकता हो सेवा निर्यात

डा. जयंती लाल भंडारी

हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पायथन वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, ब्लॉक चेन और सायबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाना होगा'

इन दिनों प्रकाशित हो रही विदेश व्यापार संबंधी नई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद गठित होने वाली भारत की नई सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह भारत की सेवा निर्यात (सर्विस एक्सपोर्ट) में दिखाई दे रही ऊंची संभावनाओं को साकार करके बढ़ते विदेश व्यापार घाटे को कम करने की डगर पर आगे बढ़े। साथ ही सेवा निर्यात बढ़ाकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) सहित नए डिजिटल कौशल से दक्ष देश की नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नए मौके भी तेजी से निर्मित करके नई पीढ़ी को नई मुस्कुराहट दे। गौरतलब है कि कल तक पूरी दुनिया में भारत का सेवा निर्यात तेज रफ्तार से बढ़ रहे चमकीले सेक्टर के रूप में रेखांकित होता रहा है, लेकिन अब भारत के इसी प्रभावी सेवा निर्यात ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुस्त रफ्तार दिखाई है। सेवा निर्यात की यह रफ्तार पिछले तीन साल में सबसे कम रही है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 776.40 अरब डॉलर रहा था। ऐसे में गत वित्त वर्ष में सेवा निर्यात 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 339.62 अरब डॉलर का रहा, जबकि वस्तु निर्यात 3.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 437.06 अरब डॉलर रहा है। निश्चित रूप से बीते कुछ वर्षों में भारत के निर्यात का एक चमकदार पहलू सेवा निर्यात रहा है। भारत ने डिजिटल माध्यम से मुहैया करायी गयीं सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डिजिटल माध्यम से सेवा निर्यात के तहत कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर शिक्षा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, गेमिंग, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित एक शोध आलेख के पिछले तीस वर्षों में यानी 1993 से 2022 के बीच भारत का सेवा निर्यात 14 फीसदी से अधिक की समेकित सालाना वृद्धि दर से बढ़ा। यह 6.8 फीसदी की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में बेहतर है। परिणामस्वरूप समान अवधि में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.5 फीसदी से बढक़र 4.3 फीसदी जा पहुंची। इसी आधार पर भारत दुनिया में सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन गया है, जबकि वर्ष 2001 में सेवा निर्यात के मामले में भारत 24वें स्थान पर था। खास बात यह भी है कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे और सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवा निर्यात में छठे स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि केवल डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई सेवाओं के निर्यात के आधार पर मूल्यांकन करें तो इस क्षेत्र में भारत जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के बाद चौथे क्रम पर आ गया है। निश्चित रूप से भारत सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। निःसंदेह भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की तेजी से नई स्थापनाओं के कारण भी सेवा निर्यात बढ़ रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वर्ष 2015-16 से लगातार वर्ष 2022-23 के बीच भारत में जीसीसी की संख्या 60 फीसदी बढक़र 1600 से अधिक हो गई है। जीसीसी भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष केंद्र हैं जिनका मकसद स्थानीय प्रतिभा का फायदा उठाना, अधिक से अधिक परिचालन दक्षता हासिल करना और नए बाजारों तक पहुंचना है। जीसीसी सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा, विश्लेषण और कारोबारी प्रक्रियाओं के संचालन सहित तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भारत में जीसीसी की आय पिछले 13 वर्षों में 11.4 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ी और चार गुना होती हुई वित्त वर्ष 2023 में 46 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीते कुछ दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम पहलू सेवा निर्यात रहा है। इसने न केवल व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद की है, बल्कि इनसे देश में रोजगार निर्माण में सहारा दिया है। भारत ने वैश्विक सेवा व्यापार में प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रदर्शित की है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में भारत की लगातार पहचान बढ़ी है। लेकिन अब सेवाओं के निर्यात में कमजोर वृद्धि की मुख्य वजह विकसित अर्थव्यवस्थाओं से मांग नरम रहना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी सेवा निर्यात की हालत कमजोर ही रहने की आशंका है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर अमेरिका एवं यूरोप में उच्च ब्याज दरों के कारण मांग में नरमी रहेगी तथा युद्धजनित परिस्थितियों से वैश्विक व्यापार में कमी आएगी। निश्चित रूप से जिस तरह से ईरान-इजराइल के बीच टकराव और दुनिया में भूराजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उससे कच्चे तेल के दाम के साथ-साथ आपूर्ति संकट बढने की चिंताएं मुंहबाए खड़ी हैं। इससे भारत के वैश्विक व्यापार व निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भारत को सेवा निर्यात बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढना होगा। चूंकि इस समय विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, यह भारतीय निर्यातकों के लिए भी चुनौती है।

लेकिन यह बात ध्यान में रखी जानी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करना होंगे। भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमें सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करके आउटसोर्सिंग की संभावनाओं वाले अन्य देशों में भी कदम बढ़ाना होंगे। खासतौर से आउटसोर्सिंग की नई संभावनाएं उत्तरी यूरोप, पूर्वी एवं मध्य यूरोप के देशों, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और पूर्वी एशियाई देशों, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में और बढ़ गई है।

भारत की आईटी सेवा कंपनियों को गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में कारोबार में आगे बढने के लिए कार्मिकों को जापानी, कोरियाई व अन्य भाषाओं में प्रशिक्षण देने पर व्यय किया जाना होगा ताकि इन देशों के बाजारों तक भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की पहुंच बनाई जा सके। अब हम उम्मीद करें कि 4 जून के बाद गठित होने वाली देश की नई सरकार देश की नई पीढ़ी को आईटी के नए दौर की शिक्षा देने के लिए समुचित निवेश की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देते हुए दिखाई देगी। हमें नए दौर की तकनीकी जरूरतों और इंडस्ट्री की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को सुसज्जित करना होगा। हमें शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढना होगा।

हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पायथन वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, ब्लॉक चेन और सायबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाना होगा। निश्चित रूप से ऐसे बहुआयामी प्रयासों से देश में सेवा निर्यात की सुस्त होती हुई रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा और सेवा निर्यात की अधिक आय से विदेश व्यापार के घाटे में कमी लाई जा सकेगी।

संपादक की कलम से

हिमाचल के सियासी गुनाह-2

हिमाचल की सियासत सुरंग से आर और पार होती रही और प्रश्नों की मिलकीयत में हमेशा शिमला के सचिवालय का व्यवहार देखा गया। ऐसे में चंडीगढ़ के पंजाब सचिवालय या पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़े पहाड़ी, जब हिमाचल में अपना ठौर बनाने लगे, तो ऊपरी से निचले हिमाचल की सरहदों में किसी ने सेब चुना, तो कोई गलगल की सडऩ में दब गया। राजनीति की अजीब नातेदारी है। यहां कुआं-कुएं से और पेड़-पेड़ से टकराते हैं। हैरानी यह कि हिमाचल में कद्दावर नेता आपस में टकरा कर राजनीति को घायल करते रहे। शांता कुमार मंत्रिमंडल में जगदेव चंद का वजन और दूसरी बार रणजीत सिंह से हुआ मुकाबला बताता है कि सियासत सबसे पहले अपनों की कब्रें खोदती रही है। चुनौती तो हिमाचल निर्माता को भी मिली और जब पंजाब के पर्वतीय इलाके प्रदेश में मिल रहे थे, तो किसी ने यह नहीं सोचा कि पौंग जलाशय से जुड़े अधिकार या बीबीएमबी की मिलकीयत में पैरोकार मिल जाएं। नतीजतन तत्कालीन हिमाचली सियासत ने इस मिलान में सियासी मिलावट देखी, वरना पंजाब पुनर्गठन के 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी से चंडीगढ़ में भी हमारा क्षेत्रीय ढांचा होता। तब राजनीति ने सुरक्षा के दायरों में शिमला में सारी सत्ता को आजमाने की कोशिश की और इस दृष्टि से पंजाब पुनर्गठन की दौलत ऐसी बिखरी कि आज तक संभल नहीं पाई। आश्चर्य है कि टिहरी गढ़वाल ने बांध परियोजना से न्यू टिहरी बसा लिया या नर्मदा परियोजना के बदले कई राज्यों ने अपने लिए नई आर्थिकी सुनिश्चित कर ली, लेकिन देश के सबसे बड़े विस्थापन यानी पौंग डैम से उजड़े तीस हजार परिवारों के बदले तत्कालीन वाईएस परमार सरकार कुछ न कह पाई।

पर्वतीय क्षेत्रों का हिमाचल में मिलना और पौंग बांध से उजडऩा लगभग एक ही समय की दो घटनाएं हैं, जहां सियासत ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए गुनाह नहीं किए, बल्कि ताकत भी खो दी। एक विधायक के रूप में डा. राजन सुशांत का ग्यारह महीने का धरना अपने आप में हिमाचली अधिकारों के प्रति एक मशाल की मानिंद था, लेकिन सियासत और समाज के पन्नों ने इसे भी मिटा दिया। यह अजीब सी बांध परियोजना न पहले हिमाचल को सींच रही थी और न इससे पैदा हुई बिजली से एक भी यूनिट प्रदेश को मिल रहा था। हमारी राजनीति में प्रदेश के नायकत्व, स्वाभिमान और स्वावलंबन को रेखांकित करने का न तो जज्बा है और न आत्मविश्वास, बल्कि ऐसी परिपाटी बन रही है कि चंद नेता अपनी ही सत्ता की बगावत में आलाकमान की जूतियां चाटकर पहलवान बनने के कौशल में प्रदेश के सियासी मुखौटे को वीभत्स कर रहे हैं। क्या एक प्रदेश की राजनीति में गुर्गे और मुर्गे चलेंगे। बेशक पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व का अपना नजरिया, राष्ट्रीय उत्कंठा और अनुशासन होगा, लेकिन हिमाचल की दृष्टि से राज्य स्तरीय नेतृत्व का कौशल अब आलाकमान की चापलूसी हो गई। कमोबेश हर राजनीतिक दल अब अपने प्रदेश प्रभारियों के मार्फत किसी न किसी गुट को प्रश्रय दे रहा है, जिसके नतीजे कमजोर सरकारें अब अपने आवरण में विश्वास पात्रों की परिधि समेटते-समेटते कुछ खास चेहरों तक सिमटने लगी हैं।

वर्तमान उपचुनावों में कौन जीते-कौन हारे, इससे शायद सत्ता और विपक्ष के बीच कोई पहाड़ न टूटे मगर, हिमाचल के राजनीतिक चरित्र को लगा घुन अब समाप्त नहीं होगा। छोटे राज्यों में हिमाचल की राजनीति ने प्रदेश को कभी भी इस तरह अस्थिर करने की जुर्रत नहीं की, लेकिन अब यह सफर हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी करेगा। ऐसे राजनीतिक गुनाह की परिणति एक चुनाव में नहीं होगी और न ही ऐसे गुण-दोष के आधार पर जनता किसी को चुनेगी या किसी को पटक देगी, लेकिन आगे की यात्रा में सियासी मंजर की स्थिति अविश्वसनीय, भ्रष्ट, विकराल, बेउसूल और बिगड़ैल तो होगी ही।

ज्ञान

बदतर होती बेरोजगारी

एक डाटा सामने आया है कि मोदी सरकार ने अपने 10 साला कार्यकाल के दौरान 51.40 करोड़ रोजगार मुहैया कराए हैं। इसमें सरकारी नौकरियां, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में नौकरियां और दिहाड़ीदार रोजगार आदि शामिल हैं। डाटा के अर्थ हैं कि हर साल औसतन 5.14 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए गए। यह भी दावा है कि 43 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा लोन दिए गए। जाहिर है कि वे भी रोजगार का एक हिस्सा हैं। सरकार की 12 परियोजनाओं के तहत 19.79 करोड़ रोजगार दिए गए। यदि यूपीए सरकार मनरेगा दिहाड़ी को रोजगार मानती थी, तो मोदी सरकार के दौरान ऐसे अवसरों को 'रोजगार' क्यों नहीं माना जा सकता। करीब 180 देशों में रोजगार का यही प्रारूप लागू है। यह भी दावा किया गया कि रोजगार की 3.35 फीसदी सालाना बढ़ोतरी दर दर्ज की गई है। इन दावों के विपरीत देश में बेरोजगारी का संकट बदतर होता जा रहा है। सरकारी आंकड़ा 6.7 फीसदी का बताया जा रहा है, लेकिन निजी सर्वेक्षण कंपनियों के निष्कर्ष हैं कि देश भर में, सभी धर्मों, समुदायों, जातियों, जमातों में बेरोजगारी का औसत 2023-24 के दौरान 8.03 फीसदी रहा है। रोजगार का यही औसत 37.18 रहा है। बहरहाल आम चुनाव के 6 चरणों में केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे सम्पन्न राज्यों से लेकर बिहार, ओडिशा, राजस्थान सरीखे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों तक बेरोजगारी सबसे बड़ी गूंज रही है। मतदाता, रिपोर्टर, चुनाव विश्लेषक, जनमत सर्वेक्षणों और पार्टी कार्यकर्ताओं आदि ने यह मुद्दा महसूस किया और उठाया है।

सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष सामने आया है कि 29 फीसदी से अधिक लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा और संकट मानते हैं, लेकिन चुनाव इस मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा, लिहाजा वे क्षुब्ध हैं। बेरोजगारी की यह निराशाजनक स्थिति कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारत के युवा बेरोजगारी की समस्या लगातार झेलते रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद यह समस्या बढ़ी और बदतर हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के ताजा डाटा के अनुसार, जनवरी-मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर, 15-29 आयु वर्ग में, 17 फीसदी रही है। सरकारी डाटा से यह करीब तीन गुना ज्यादा है। इस आयु-वर्ग में दहाई में बेरोजगारी का संकट पिछले कई सालों से गहराता जा रहा है। दरअसल अवैतनिक काम बढ़ रहा है, गैर-श्वेत कॉलर के काम (हुनरमंद श्रम) घट रहे हैं, स्वरोजगार एक अंतिम विकल्प है, उसमें भी कम आय वर्ग वालों को घाटा ही हो रहा है। असल दिहाड़ी भी मिलना मुश्किल है। यह स्थिति तब है, जब औसतन 50 लाख लोग सालाना कार्यबल में शामिल हो रहे हैं। भारत की औसतन रोजगार दर, बीते आठ सालों के दौरान, 5.6 फीसदी गिरी है। श्रम बल भागीदारी दर के मद्देनजर देखें, तो सवर्णों में हिंदुओं की भागीदारी दर सबसे कम है। ओबीसी और अनुसूचित जातियों, जो दो सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी हैं, उनमें सबसे तेज गिरावट देखी गई है। बेरोजगारी के कई बुनियादी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सरकारी नौकरियां बेहद सीमित हैं।

वे मायावी-सी हैं, दुष्प्राप्य हैं, 144 करोड़ के देश के हरेक पात्र नागरिक को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। उसका माफिया भी देश में सक्रिय है। देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय कुकुरमुत्तों की तरह फैल गए हैं। यह भी एक विस्फोटक स्थिति है। वे अधकचरे स्नातक पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। सभी की प्राथमिकता सरकारी नौकरी की है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार बेरोजगारी को नियंत्रित कैसे कर सकती है? ऐसे में कई युवा रोजगार-घोटालों के शिकार होते हैं, विदेश भेज कर उन्हें सीधा युद्ध के मैदान में उतार दिया जाता है, नतीजतन कुछ युवा तो अनाम मौत के शिकार हुए हैं। ऐसा ही रूस का एक मामला सामने आया था। उसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप भी किया था।

सियासी शोरगुल में मतदाताओं की खामोशी

चुनावी दौर में मतदाताओं की खामोशी तथा प्रजातंत्र की ताकत युवा वेग के चेहरे पर उदासीनता की झलक जम्हूरियत की तबीयत को नासाज कर देगी। बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकती है

देश में तवील अर्से के बाद संयोग बना है कि लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनाव तथा लोकप्रियता की बुलंदी को छूने वाले खेल क्रिकेट आईपीएल का शंखनाद एक साथ हुआ। आईपीएल का फाइनल 26 मई 2024 को सम्पन्न हो गया। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे सियासी संग्राम का परिणाम चार जून 2024 को ईवीएम से बाहर आएगा। क्रिकेट व सियासत का आपस में गहरा नाता तथा समानताएं रही हैं। दोनों ही खेल धनबल, कूटनीति व रणनीति से लबरेज तथा आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। चुनाव हों या आईपीएल सरीखे टूर्नामेंट, हजारों करोड़ रुपए दांव पर लगे होते हैं। नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म रहता है। सियासी शंतरज के माहिर खिलाड़ी सियासी रहनुमां मैदान-ए-सियासत में पलटी मार कर कब किस सियासी जमात में शामिल हो जाएं, पता नहीं। वहीं आईपीएल में कौनसा खिलाड़ी भविष्य में किस टीम का हिस्सा बन जाए, यह भी तय नहीं। क्रिकेटर हों या सियासी रहनुमां, देश में दोनों का रुतबा आम लोगों से ऊपर माना जाता है। सियासत में वर्चस्व बरकरार रखने व क्रिकेट में बादशाहत कायम रखने के लिए जुबानी जंग का दौर भी जारी रहता है। दोनों ही खेलों में परिणाम के बाद पलकों से जज्बातों का सैलाब भी छलकता है। चुनावी फिजाओं का रुख भांपने में माहिर सियासी वैज्ञानिक तथा क्रिकेट के पंडित न्यूज चैनलों पर अक्सर मौजूद रहते हैं।

जिस प्रकार क्रिकेट लोकप्रियता की बुलंदी पर काबिज हो चुका है, ठीक उसी प्रकार सियासत भी राष्ट्रीय खेल का रूप ले चुकी है। कई पूर्व नौकरशाह, सिल्वर स्क्रीन के अदाकार, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तथा मजहब के रहनुमां देश का पसंदीदा खेल बन चुकी सियासत में किस्मत आजमा कर जम्हूरियत की पंचायतों की शोभा बढ़ा चुके हैं तथा कई पहुंचने को बेताब हैं। सैकड़ों इंकलाबी युवाओं की कुर्बानियों के बाद बर्तानियां हुकूमत का सूर्यास्त हुआ तथा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई थी, लेकिन सियासत के बढ़ते खुमार के आगे देश के लिए राष्ट्रवाद के मजमून लिखकर जम्हूरी निजाम बहाल करने में कुर्बानियां देने वाले इंकलाबी चेहरे इतिहास में गुमनाम हो गए। वहीं अंग्रेजों की खेल विरासत क्रिकेट की लोकप्रियता ने अन्य खेलों व खिलाडियों को हाशिए पर धकेल दिया है। हमारे देश की करोड़ों आबादी बीपीएल की श्रेणी में जीवनयापन कर रही है, मगर विदेशी खिलाड़ी व कोच हर वर्ष आईपीएल में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देश का लगभग प्रत्येक राज्य हजारों करोड़ रुपय का कर्ज लेकर 'चार्वाक' के सिद्धांत का अनुसरण पूरी शिद्दत से कर रहा है। लेकिन इक्तदार हासिल करने के लिए लोकलुभावन वादे न किए जाएं, तो सियासत की तासीर बिगड़ जाती है। जबकि सियासत का मिजाज बन चुके अधूरे सियासी वादों से परेशान होकर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विपक्ष में बैठकर सभी सियासी रहनुमां बेरोजगारी व महंगाई पर जोरदार ताकीद पेश करते हैं। बेशक प्रजातंत्र का सरमाया देश का शिक्षित वर्ग बेरोजगारी के सैलाब में फंस चुका है। आम लोग आसमान छू रही महंगाई से जूझ रहे हैं।

लेकिन बेरोजगारी व महंगाई के बढऩे के कारणों पर कभी तफसील से मंथन नहीं होता। चुनावी प्रचार के दौरान सियासी दल युवाओं को सरकारी नौकरियों के हसीन ख्वाब दिखाते हैं, नतीजतन युवा वर्ग रोजगार के लिए सरकारों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। दूसरी विडंबना यह है कि भारत में 'लार्ड मैकाले' द्वारा ईजाद किया गया तालिमी निजाम शारीरिक परिश्रम व जमीनी स्तर की मेहनत के बजाय सरकारी नौकरी को ज्यादा तरजीह देता है। इसी कारण अंग्रेजी झाडऩे वाली अफसरशाही तथा सियासी व्यवस्था धरातल पर सोज-ए-वतन की हकीकत से मुखातिब होने में नाकाम रही है। प्रजातंत्र की बुनियाद डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं के हिज्र का दर्द तथा करोड़ों आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले अन्नदाता किसानों की संवेदनाएं समझने में मुल्क का सियासी निजाम विफल रहा है। बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार से बढ़ रही जनसंख्या है। वोट बैंक की सियासत के चलते बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के मुद्दे पर सियासी दल गुफ्तगू करने से परहेज करते हैं। मुफ्तखोरी की भूमिका पर अंकुश लगाना मुश्किल हो चुका है। जिस तीव्रता से देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उतने रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है।

देश की सियासत ज्यादातर जाति, मजहब, आरक्षण, मुफ्तखोरी की खैरात, आरोप-प्रत्यारोप, दलबदल, चुनावी मंचों से जहरीली तकरीरें व विवादित बयानबाजी की तवाफ करती है, जबकि आम लोगों की कई समस्याएं चुनावी शोरगुल में दब कर रह जाती हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार सिस्टम में पैर पसार चुका है। रोजगार की तलाश में प्रतिभाएं देश से पलायन कर रही हैं। नशे के सरगना युवा पीढ़ी का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। लाखों गोवंश सडक़ों पर अपना भाग्य कोस रहा है। अतः प्रजातंत्र के इन मुद्दों पर भी सियासी नजर-ए-करम की जरूरत है। सियासत में जोर आजमाईश का मकसद केवल सत्ता की दहलीज पर पहुंचने के लिए नहीं होना चाहिए। चुनाव अंतिम चरण में है, मगर इस बार चुनावी शोरगुल के दौरान मतदाताओं में खामोशी की रजामंदी का आलम रहा है।

लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना पड़ा। निर्वाचन आयोग को भी मतदान के लिए लोगों से अपील करनी पड़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की ताकत से ही देश की दिशा तय होती है। अलबत्ता जब पड़ोस में चीन व पाकिस्तान जैसे नामुराद मुल्क मौजूद हों, तो देश के सियासी नेतृत्व का चुनाव सशक्त व दमदार प्रत्याशी के तौर पर होना चाहिए। बहरहाल चुनावी दौर में मतदाताओं की खामोशी तथा प्रजातंत्र की ताकत युवा वेग के चेहरे पर उदासीनता की झलक जम्हूरियत की तबीयत को नासाज कर देगी। बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी देश में सामाजिक अस्थिरता का तनाजुर पैदा कर सकती है। लिहाजा मुफ्तखोरी की योजनाओं के बजाय युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम होना चाहिए।

शव संवाद-45

सेंकते-सेंकते यह रोटी इतनी लाल हो चुकी है कि किसी के गाल को भी लाल कर सकती है, लेकिन हर चूल्हा एक जैसा नहीं होता। चूल्हे सदियों से बदलते रहे। चूल्हों का अपना इतिहास है, इनके ऊपर चढ़ कर ही कभी नमक हलाल हुआ, तो कभी पूरा का पूरा चूल्हा हराम हो गया। रोटी ने हमेशा मेहनत की ताकि इसे कोई लांछन न लगे, इसलिए पैदा करने वाले से नहीं, इसे सेंकने वाले से डर लगता है। रोटी सपनों का जीवित जीवाश्म है। यह सदाचारी, ब्रह्मचारी और कर्तव्यगामिनी है। इसलिए हर कोई रोटी का भक्त हो जाता है। ताज्जुब यह कि सियासत ने इसे भी अपना भक्त बना लिया। रोटी का जिक्र सियासत का अमृत है, इसलिए इसके इशारे पर पकती और बंटती है। उन दिन मुफ्त के राशन से निकले आटे की रोटी इतनी फूली कि सियासी चूल्हे पर बवाल आ गया। गजब यह कि पकाने वाली गरीब जनता को भी यह मालूम नहीं कि वास्तव में इसे पका कौन रहा है। मजदूर के डिब्बे में दिहाड़ी की रोटी अक्सर उछल जाती है। उस दिन उछली, तो मजदूर ने उसकी इज्जत बचाने की कोशिश में मेहनत की और खूब पसीना बहाया। यह पूरी दिहाड़ी की आधी रोटी थी, लेकिन इसके साथ भारत की इच्छाएं पूरी थीं। मजदूर ने खाने से पहले इसे प्रणाम किया, तो नजर सामने दीवार पर टंगे पोस्टर पर यकायक चली गई, जहां देश उसे आदेश दे रहा था कि वह अयोध्या मंदिर निर्माण को प्रणाम करे कि आधी रोटी मिल गई। आश्चर्य यह कि वहां एक साथ मजदूरों के टिफिन से निकली रोटियां इसको लेकर झगडऩे लगीं।

उस दिन रोटियां चौराहे पर लड़ रही थीं। दरअसल रोटियों को एक मदारी लड़ा रहा था। पहली बार मदारी अपने लिए रोटियां सेंक रहा था। वह रोटी का जादूगर है। सिर्फ मैजिक से रोटी दिखाता और फिर असली नकली के भेद में इन्हें लड़ाता। कई चिकनी चुपड़ी थीं, तो कई सूखी और गरीब के गाल की तरह। रोटियों की लड़ाई भी अजीब है। ये धर्म-जाति नहीं जानतीं, मगर इनसान और दौलत का रिश्ता खूब पहचानती हैं। झगड़ रही रोटियों को एक समझदार रोटी समझा रही थी, उन्हें आपस में लडऩे से बचा रही थी। यह बुद्धिजीवी की रोटी थी जो भूख का राष्ट्रवाद जानती थी, 'देखो बहनों, हमारा जन्म भले ही अब यशस्वी नहीं रहा, लेकिन हमें सेंक कर ही देश चल रहा है। हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी पीठ पर चढक़र हर कोई सियासत सेंक रहा है। एक रोटी है, जो खाने वाले की नस्ल के लिए प्राण तक त्याग देती है।' अपनी रोटी की भाषा, उसकी देह भाषा और उसका वजूद देखकर पास खड़ा बुद्धिजीवी हैरान था कि उसे नसीब हुई सूखी रोटी भी कितने सौहार्द से भरी है। उसकी रोटी बासी थी, लेकिन फिर भी रोटी थी, वरना जमाना जो खा रहा है, वह अब रोटी है ही कहां। बुद्धिजीवी की रोटी से कहीं भिन्न भारत की रोटी थी, जिसे सेंक कर कई नेता, विजेता बन गए। अचानक बाकी रोटियां दौडऩे लगीं।

रोटियां आगे-आगे और देश पीछे-पीछे। बुद्धिजीवी की समझदार रोटी बातें तो कर सकती थी, लेकिन दौड़ के काबिल नहीं थी। उसने किसान आंदोलन में इसी तरह रोटियों का संघर्ष देखा है। उसने बेरोजगारों के बीच रोटी का शर्मनाक चेहरा देखा है। रोटी की कोख से गरीब की जिंदगी का सौदा और क्या होगा कि मुफ्त का राशन बांटने वाला, चुपचाप सियासी रोटी सेंक गया। बुद्धिजीवी की रोटी यह सब देखकर बुरी तरह झुलस गई थी। बुद्धिजीवी हर बार की तरह इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोटी के लिए बुद्धि हार गई। लड़ती-झगड़ती रोटियां भाग रही थीं और देश खुश था कि इस तरह मीलों दूर भागने का उसे बहाना मिल गया, लेकिन इस बीच बुद्धिजीवी के हिस्से की रोटी बुरी तरह रौंदी जा चुकी थी। उसकी आहें धीरे-धीरे खत्म हो गईं।

मुंबई में बनी इस सुरंग से बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी, साल 2026 से है चलाने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

इस नई सुरंग के लिए खुदाई का काम 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था और छह महीने में 394 मीटर की पूरी लंबाई की खुदाई कर ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तत्कालीन जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में इस परियोजना का शुभारंभ किया था। नवंबर 2021 में काम शुरू होने के बाद से मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लगातार प्रगति कर रहा है।

नई दिल्ली। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत चल रहे काम में तेजी लाने के लिए, मुंबई के घनसोली में 394 मीटर लंबी एक अतिरिक्त मध्यवर्ती सुरंग बनाई गई है। इस नई मध्यवर्ती सुरंग की वजह से बीकेसी और ठाणे खाड़ी से सटे शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

26 मीटर गहरा नया टर्मिनल 3.3 किलोमीटर लंबा है, और यह दोनों तरफ 1.6 मीटर (लगभग) सुरंग बनाने के लिए एक साथ पहुंच प्रदान करेगा। बुलेट ट्रेन परियोजना को अंजाम देने वाली स्पेशल पर्पस कंपनी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 21 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग के लिए, 16 किलोमीटर सुरंग बोरिंग मशीनों का उपयोग करके खोदी गई है और बचे हुए 5 किलोमीटर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि के माध्यम से खोदी जाएगी।

6 दिसंबर को शुरू हुआ था काम

इस नई सुरंग के लिए खुदाई का काम 6 दिसंबर, 2023 को शुरू हुआ था और छह महीने में 394 मीटर की पूरी लंबाई की खुदाई कर ली गई। इस काम के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में 27,515 किलोग्राम विस्फोटकों का उपयोग करके कुल 214 नियंत्रित विस्फोट किए गए। इस नई सुरंग की लंबाई-चौड़ाई ऐसी है कि इससे न केवल निर्माण बल्कि संचालन के दौरान भी मुख्य सुरंग तक वाहन सीधे पहुंच सकेंगे और इमरजेंसी की स्थिति में निकासी प्रक्रिया के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।

तेजी से हो रहा 21 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग का काम

मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन से महाराष्ट्र के शिलफाटा तक 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस सुरंग का करीब सात किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक में समुद्र के नीचे होगा। यह देश में कहीं भी बनने वाली अपनी तरह की पहली सुरंग है। 21 किलोमीटर लंबी यह सुरंग सिंगल ट्यूब सुरंग होगी जिसमें ऊपर और नीचे दो ट्रैक होंगे। वर्तमान में, सुरंग बोरिंग मशीनों का उपयोग करके बीकेसी, विक्रोली और सावली में 16 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है।

320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार

सुरंग के अंदर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। इस साल मार्च में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना 2026 तक तैयार हो जाएगी, जिसमें शुरुआत में सूरत और बिलिमोरा के बीच ट्रेन चलेगी। नवंबर 2021 में काम शुरू होने के बाद से मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लगातार प्रगति कर रहा है। बता दें कि भूमि अधिग्रहण में चुनौतियों के कारण परियोजना को शुरू में देरी का सामना करना पड़ा।

2017 में हुआ था परियोजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तत्कालीन जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 14 सितंबर, 2017 को अहमदाबाद में इस परियोजना का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को 12 फरवरी 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्तपोषण, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के उद्देश्य से जोड़ा गया था।

शेयर बाजार के ऑनलाइन एक्सपर्ट से सावधान! ये लालच देकर साफ कर रहे लोगों का बैंक अकाउंट

परिवहन विशेष न्यूज

वॉट्सऐप समेत इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में सक्रिय हैं जो हर दिन निवेशकों को बेहतर रिटर्न का टिप्स देते नजर आते हैं। लेकिन इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये साइबर ठग भी हो सकते हैं। आई4सी पर साइबर ठगी की मिल रही शिकायतों में बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न का झांसा देकर होनी वाली ठगी की है।

नई दिल्ली। वॉट्सऐप समेत इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर शेयर बाजार के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, जो हर दिन निवेशकों को बेहतर रिटर्न का टिप्स देते नजर आते हैं। लेकिन इन विशेषज्ञों से सावधान रहने की जरूरत है। ये साइबर ठग भी हो सकते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) पर साइबर ठगी की मिल रही शिकायतों में बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न का झांसा देकर होनी वाली ठगी की है।

समस्या यह है कि इसे रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर तंत्र विकसित नहीं हो पाया है। आरबीआई जहां इसके लिए जागरुकता अभियान चलाने पर जोर दे रहा है, वहीं सेबी शेयर बाजार के एक्सपर्ट के लिए नई गाइडलाइंस लाने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक्सपर्ट के पंजीकरण भी शामिल है।

कैसे ठगी को अंजाम देते हैं साइबर ठग

आई4सी के सीईओ राजेश कुमार के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में सक्रिय संगठित साइबर ठगों का गिरोह शेयर बाजार के एक्सपर्ट का झांसा देकर लोगों के निवेश के लिए बरगलाते हैं और शुरुआत में उन्हें लाभ होता दिखाते भी हैं। शेयर बाजार के बारे में इन साइबर ठगों की जानकारी को देखते हुए लोग आसानी से उनकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई की रकम को बेहतर रिटर्न के लालच में उनके कहने पर निवेश कर देते हैं।

जबतक निवेशक को ठगी का एहसास होता है, तबतक बहुत देर हो चुकी होती है। निवेश का पैसा बैंकिंग से चैनल से बाहर जा चुका होता है। इसे क्रिप्टो कैरेंसी या फिर हवाला जरिये साइबर ठग दूसरे देश में पहुंचा चुके होते हैं। यही कारण है कि शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में रिकवरी की संभावना बहुत कम रह जाती है। एजेंसियां उतनी रकम फ्रीज करने में सफल होती है, जो बैंकिंग चैनल से बाहर जाने के बच जाता है।

साइबर ठगी के लिए गाइडलाइंस की तैयारी

इंटरनेट मीडिया पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट की बढ़ती संख्या और इसके माध्यम से आम निवेशकों की ठगी के बढ़ते मामलों के देखते हुए गृहमंत्रालय के मातहत आने वाला आई4सी के साथ-साथ सेबी और आरबीआई जैसी वित्तीय एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। सेबी ने पिछले साल इसके लिए ड्राफ्ट पेपर तैयार किया था, जिसमें ऐसे एक्सपर्ट के लिए गाइडलाइंस बनाने का बात शामिल है।

माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद इस गाइडलाइंस को जारी कर दिया जाएगा। गाइडलाइंस में शेयर बाजार के एक्सपर्ट के लिए पंजीकरण को अनिवार्य करने का प्रविधान भी हो सकता है। वहीं आई4सी भी आरबीआई की तरह निवेशकों की जागरूकता को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।

आई4सी के सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि वे नियामक एजेंसियों के मिलकर इसे रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रविधान करने पर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी जरा भी आशंका होने पर तत्काल साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबरक्राइमडाटजीओवीडाटइन पर इसकी सूचना देनी चाहिए। इससे संबंधित ठगी के एक्सपर्ट के वीडियो और लिंक को ब्लाक किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अन्य कदम उठाये जा सकते हैं।

NSE ने टिक साइज घटाने का किया एलान, जानिए निवेशकों को क्या होगा फायदा

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 250 रुपये प्रति शेयर से कम कीमत वाले सभी शेयरों के लिए टिक साइज यानी न्यूनतम मूल्य अंतर को 5 पैसे से घटाकर 1 पैसा करने का फैसला किया है। यह फैसला 10 जून से लागू होगा। इससे लिक्विडिटी तो बढ़ेगी ही, प्राइस एडजस्टमेंट भी हासिल होगा। यह बदलाव टी+1 सेटलमेंट के तहत आने वाली सिक्योरिटीज पर भी लागू होगा। एनएसई हर महीने टिक साइज का रिव्यू करेगा।

टिक साइज क्या होता है?

टिक साइज दो लगातार बाय और सेल प्राइस के बीच का मिनिमम प्राइस इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है कि टिक साइज जितना छोटा होगा, प्राइस एडजस्टमेंट भी उतना ही सटीक होगा। साथ ही, बेहतर प्राइस निकलकर सामने आएगी। मिसाल के लिए, किसी स्टॉक का टिक प्राइस 0.10 रुपये और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 50 रुपये है, तो अगला बाय प्राइस 49.90, 49.80, 49.70 रुपये की सीरीज में होगा।

इस स्थिति में बिड प्राइस 49.75 या 49.72 रुपये नहीं हो सकती, क्योंकि यह 10 पैसे टिक साइज के मापदंड के खिलाफ हो जाती है। लेकिन, 1 रुपये की टिक साइज के साथ यह असुविधा दूर हो जाएगी और निवेशक ज्यादा बेहतर तरीके से शेयर खरीद और बेच सकेंगे।

टिक साइज बदलने का असर?

एक्सपर्ट का कहना है कि इस बदलाव के बाद NSE का प्राइसिंग सिस्टम भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के बराबर हो जाएगा। बीएसई ने मार्च 2023 में ही 100 रुपये से कम कीमत वाले स्टॉक का टिक साइज 1 पैसा कर दिया था। टिक साइज कम करने से से मार्केट में बेहतर प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी और ज्यादा बेहतर ट्रेडिंग सिस्टम तैयार हो सकता है। एनएसई और बीएसई भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। अगर एशिया की बात करें, तो जापान, चीन और हांगकांग के बाद सबसे बड़े हैं।

स्पेक्ट्रम शुल्क की किस्तों के साथ करना होगा GST का भुगतान, 6 जून को नीलामी का अगला दौर

लेखा और परामर्श कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत स्पेक्ट्रम भुगतान अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं के अंतर्गत आता है जिसपर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है। मोहन ने कहा स्पेक्ट्रम शुल्क एक निश्चित अवधि में चरणबद्ध तरीके से अदा करना होता है।

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के साथ-साथ जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। एक अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को प्रत्येक किस्त के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी का अगला दौर छह जून को आयोजित करेगा।

नीलामी के लिए आधार मूल्य 96,317 करोड़ रुपये तय किया गया है। स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए आवंटित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को आगामी 'मेगा' नीलामी में 20 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।

जीएसटी परिषद स्पष्ट करेगी भुगतान की प्रक्रिया

अधिकारी ने कहा, 'जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान बोली जीतने वाली कंपनियों द्वारा जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकती है।' स्पष्टीकरण से नीलामी प्रक्रिया में जीएसटी संग्रह की विधि के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच भ्रम समाप्त हो जाएगा।

लेखा और परामर्श कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत स्पेक्ट्रम भुगतान अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिसपर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है। मोहन ने कहा, 'स्पेक्ट्रम शुल्क एक निश्चित अवधि में चरणबद्ध तरीके से अदा करना होता है। इस प्रकार कर भुगतान भी अलग-अलग होगा। निदेशक मंडल को इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए ताकि इस संबंध में किसी भी मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

RBI ने सरकार को दिया रिकॉर्ड डिविडेंड, क्या जारी रहेगा यह सिलसिला? अमेरिकी रेटिंग एजेंसी से मिला जवाब

नई दिल्ली। अमेरिका की प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी- फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) का कहना है कि इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर किया है, जो भारत की जीडीपी का तकरीबन 0.6 फीसदी हिस्सा बनता है। लेकिन, RBI के लिए सरकार को हर बार इतना डिविडेंड दे पाना मुश्किल होगा।

RBI ने कितना डिविडेंड दिया? रिजर्व बैंक के बोर्ड ने पिछले हफ्ते सरकार को रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड ट्रांसफर करने का फैसला किया था। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जो मुनाफा कमाया था, उसी से यह डिविडेंड दिया है। यह सरकार के निर्धारित बजट 1.02 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है।

क्या कहना है फिच रेटिंग्स का? फिच रेटिंग्स के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने अपने मुनाफे का अभी सिलसिलेवार ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन, माना जा रहा है कि उसे फॉरेन एसेट पर काफी ऊंचा ब्याज मिला है, जिससे उसकी कमाई में इजाफा हुआ है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का इस देश में भी बजेगा डंका; तैयार करेगी 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के प्रमुख मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में दबदबा बनाने के अब अफ्रीकी मार्केट में एंट्री करने वाली है। दरअसल अफ्रीकी देश घाना ने रिलायंस जियो की सब्सिडियरी टेक महिंद्रा और दूसरे वेंडर्स के साथ देश में 4जी और 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए डील साइन की है। घाना ने चीन के जाल में फंसने के बजाय भारतीय वेंडर्स के साथ डील की है।

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के प्रमुख मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में दबदबा बनाने के अब अफ्रीकी मार्केट में एंट्री करने वाली है। दरअसल, अफ्रीकी देश घाना ने रिलायंस जियो की सब्सिडियरी, टेक महिंद्रा और दूसरे वेंडर्स के साथ देश में 4जी और 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए डील साइन की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह टोटल डील 20 करोड़ डॉलर से अधिक की है।

क्या है घाना का प्लान?

घाना अब अपनी टेलीकॉम क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है। वहां की पब्लिक सेक्टर की नेक्स्ट-जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (NGIC) ने रिलायंस जियो की सहयोगी कंपनी Radisys, टेक महिंद्रा और नोकिया के साझेदारी की है। इसका मकसद देश में किफायती 5जी मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।

NGIC को 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है और स्थानीय दूरसंचार कंपनियां अगले छह महीनों में सेवाएं शुरू करने के लिए साझा बुनियादी ढांचे का उपयोग करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार, यह टोटल डील 20 करोड़ डॉलर से अधिक की है।

घाना ने की भारत की तारीफ

इस पश्चिमी अफ्रीकी देश के कम्युनिकेशन और डिजिटलाइजेशन मंत्री Ursula Owusu-Ekuful ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत हमारी 'रणनीतिक पसंद' है, क्योंकि घाना और भारत की जनसांख्यिकीय कमोबेश एक जैसी ही है। साथ ही, भारत ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कामयाबी की दास्तान लिखी है, उसे हम दोहराना भी चाहते हैं।

Ursula ने कहा, 'भारत की जनसांख्यिकीय बिल्कुल हमारे जैसी है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर की दिशा और दशा बदलने वाला जियो मॉडल बस कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था। लिहाजा, वह मॉडल अभी भी बिल्कुल ताजा है और हम उस कहानी को घाना में दोहरा सकते हैं।'

चीन के बजाय भारत को चुना

एकुफुल ने कहा कि घाना 33 देशों के स्मार्ट अफ्रीका अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में महाद्वीप के अन्य देश भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बारीक नजर रखेंगे, क्योंकि वे जानना चाहेंगे कि उनके देश में भी इस मॉडल पर अमल कर सकता है या नहीं।

घाना के मंत्री से सवाल किया गया कि भारतीय वेंडर्स ने पहले कभी ऐसी डील नहीं की है। वहीं, चीनी सप्लायर्स को इस क्षेत्र में काफी अनुभव है, तो उन्होंने चीन के बजाय भारत को क्यों चुना।

इसका जवाब देते हुए एकुफुल ने कहा, 'भारत हमारे लिए एक रणनीतिक विकल्प था। हम किसी भी भू-राजनीति में फंसना नहीं चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए सर्वोत्तम हो। हमारा मकसद इस क्षेत्र में भारत के अनुभव का लाभ उठाना है।'

एलन मस्क के साथ भी बातचीत

घाना के मंत्री ने कहा कि हम अपने टेलीकॉम सेक्टर को बेहतर करने के लिए 4जी और 5जी नेटवर्क के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत में Jio की प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे प्रमुख मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों में से एक है।

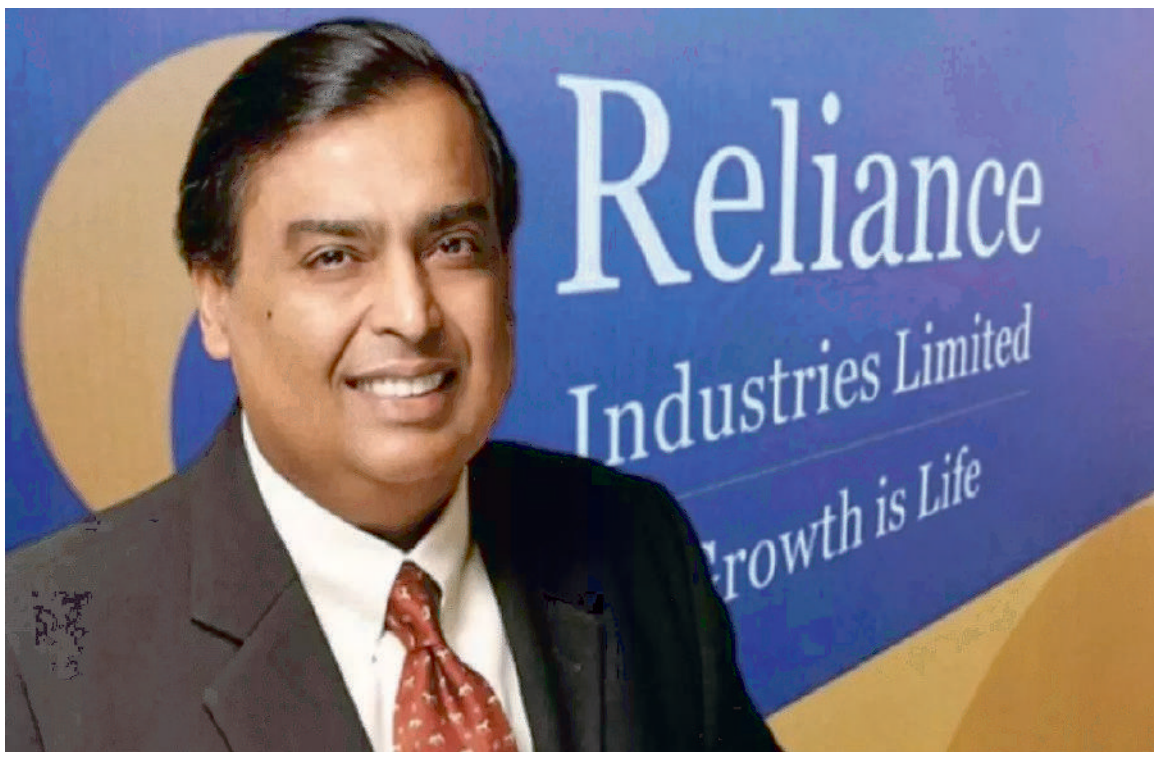

ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का ट्रायल करेगी सेना, जानें इसकी खासियत

देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मंत्रालय की पहल के तहत दिल्ली में पिछले साल पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई थी। अब सेना ने एक बस ट्रायल के लिए ली है।

नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस तैयार करके स्वच्छ ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया था। यह अभूतपूर्व पहल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देते हुए जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सेना प्रमुख मनोज पांडे ने हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल बस को ट्रायल के लिए लिया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बस का ट्रायल करना जरूरी है।

साझेदारी लगभग छह से सात दशक पुरानी

सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा, 'इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारतीय सेना के बीच साझेदारी लगभग छह से सात दशक पुरानी है। मुझे लगता है कि यह रिश्ता हम दोनों के बीच विश्वास के अटूट बंधन पर आधारित है और एक बहुत ही ठोस नींव पर भी आधारित है। मुझे खुशी है कि अब हम इसे अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, जिसमें सरकार के 2023 के नए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के आधार पर, आईओसी ने टाटा मोटर्स की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की है। अब हम पहली 15 बसों में से एक का ट्रायल करने जा रहे हैं।'

देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पिछले साल हुई थी लॉन्च

गौरतलब है, पिछले साल केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मंत्रालय की पहल के तहत दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है जो भारत को अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि सरकार जल्द ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है, जिसमें भारत को डीकार्बोनाइजेशन टार्गेट को पूरा करने में मदद करने की आपार क्षमता है और 2050 तक हाइड्रोजन की ग्लोबल मांग चार से सात गुना बढ़कर 500-

800 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

क्या है इस बस की खासियत

ग्रीन हाइड्रोजन बस एक शून्य-उत्सर्जन वाहन है जो बस को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल करता है, जिसमें सिर्फ पानी का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया एनोड पर फ्यूल (हाइड्रोजन) और कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन को पानी में बदलती है और इलेक्ट्रॉनों के रूप में विद्युत ऊर्जा पैदा करती है। बैटरी वाहनों की तुलना में फ्यूल सेल वाहनों में लंबी दूरी और कम ईंधन भरने की जरूरत होती है।

ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस

इंडियन ऑयल ने दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निर्धारित रास्तों पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 15 फ्यूल सेल बसों के परिचालन परीक्षण की शुरुआत करने की पहल की है। दिल्ली के इंडिया गेट से सबसे पहले दो फ्यूल सेल बसों का शुभारंभ किया जा रहा है। इंडियन ऑयल ने आरएंडडी फरीदाबाद परिसर में एक अत्याधुनिक वितरण सुविधा भी स्थापित की है जो सौर पीवी पैनलों का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल दे सकती है।

बगैर ड्राइवर के चल पड़ी राजस्थान रोडवेज की बस, मौके पर मौजूद शख्स की सूझबूझ से टला हादसा

जयपुर। बाड़मेर में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की एक बस बगैर ड्राइवर के ही चल पड़ी। सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति ने बस का दरवाजा खोलकर हाथ से ब्रेक लगाया अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिना ड्राइवर की इस बस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी तो भारत में बिना ड्राइवर की गाड़ियां लांच भी नहीं हुईं, उसके पहले ही राजस्थान रोडवेज की एक बस बिना ड्राइवर के चल दी। वहां मौजूद एक शख्स ने तुरंत बस का दरवाजा खोलकर ब्रेक लगाया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बाड़मेर बस स्टैंड पर चली इस बिना ड्राइवर की बस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बस के अचानक चल पड़ने से हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ लेकिन इससे चालक की लापरवाही जरूर उजागर हुई है। अब तक बस के अचानक चलने के पीछे के कारणों का पता नहीं चला है लेकिन यदि बस रोकने वाले शख्स ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो जनहानि भी हो सकती थी।

फेम ने सिंधी बाजार के व्यापारियों के साथ दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन

फेम व्यापारियों के हर सुख दुःख में उनके साथ रहेगा : राजेश खुराना (फेम जिलाध्यक्ष)

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। आज फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल, आगरा ने जिलाधिकारी के माध्यम से उ.प्र. के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा। जिसे जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कलेक्ट्रेट के प्रशासिनक अधिकारी विनय कुमार जैन ने लिया।

आज प्रातः पूर्वघोषणा के अनुसार फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल राजेश खुराना (जिलाध्यक्ष) एवं ब्रजेश पंडित (महामंत्री) के नेतृत्व में सिंधी बाजार के पीड़ति व्यापारियों को साथ लेकर जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट स्तिथ कार्यालय पर पहुंचा। जहां अधिकारियों की एन.आई.सी. की बैठक होने के कारण कलेक्टरेट के प्रशासनिक अधिकारी विनय जैन ने ज्ञापन लिया। फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल जो व्यापारियों का राष्ट्रीय संघ है, जो देश के 21 राज्यों में एवं 400 जिलों में अपनी मजबूत स्तिथि रखता है। अपने ज्ञापन में फेम ने मुख्य रूप से व्यापारियों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता, भवननिर्माण के लिए आगरा विकास प्राधिकरण की सहायता,

विद्युत विभाग से पुनर्संयोजन, फिक्स चार्ज, एवं बिल माफी एवं जी.एस.टी.विभाग से विलंब शुल्क इत्यादि की मांग मुख्य रूप से रखीं।

इस अवसर पर राजेश खुराना ने पीड़ति व्यापारियों से हालातों का जायजा लिया एवं जिस तरह सरकार किसानों एवं अन्य लोगो की मदद करती है उसी प्रकार व्यापारियों की मदद के लिए मांग रखी और कहा 'फेम व्यापारियों के हर सुख दुःख में उनके साथ रहेगा'। इसी क्रम में महामंत्री ब्रजेश पंडित ने बताया कि व्यापारियों द्वारा सरकार को टैक्स के रूप में सरकार को बड़ा योगदान रहता है, उसी के मद्देनजर ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व है कि इस संकट की घड़ी में सरकार व्यापारियों के पुनर्वास के लिए हर संभव मदद करे एवं इस संदर्भ में ओर भी आगे की कार्यवाही करेगा।

प्रतिनिधिमंडल में फेम से राजेश खुराना, ब्रजेश पंडित, शिवम गर्ग, धर्मवीर कौशिक, मुकेश निर्वाणिया, प्रेम शर्मा एवं सिंधी बाजार के पीड़ति व्यापारी जमुनादास, पंकज कुमार, असलम खान, ललित कुमार, अक्षय गुप्ता, बंटी गुप्ता, पंकज मनचंदा, जयंत कुमार आदि उपस्थित रहे।

असम में सापों की बड़ी खेप बरामद, प्लास्टिक के बरतन में रेंगते मिले दर्जनों नवजात

पूर्वोत्तर राज्य असम में सोमवार को दुर्लभ सापों की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। यह सापों की खेप असम के नागांव जिले के कलियाबोर इलाके में एक घर में पाए गए हैं। सांपों को पशु प्रेमी संजीब डेका ने बरामद है। संजीब पेशे से पशु प्रेमी हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है।

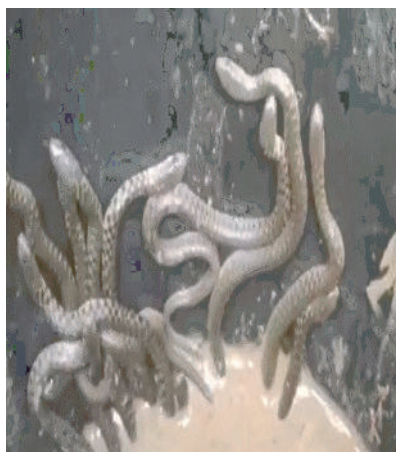

असम। पूर्वोत्तर राज्य असम में सोमवार को दुर्लभ सापों की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। यह सापों की खेप असम के नागांव जिले के कलियाबोर इलाके में एक घर में पाए गए हैं। सांपों को पशु प्रेमी संजीब डेका ने बरामद है। संजीब पेशे से पशु प्रेमी हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में प्लास्टिक के बरतन में रखे 35 सापों के बच्चे रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हापत गांव में बिजली कर्मचारीयों की लापरवाही से ट्रांसफार्मर में आग लगी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजस्थान पाली सोजत तहसील के गांव हापत देवासीयों की ढाणी में हनुमान राम देवासी हापत ने बताया कि गर्मी में ट्रांसफर में लगी आग स्थानीय ग्राम वासियों कल रात को ट्रांसफर में से चिंगारियां उसलने पर कर्मचारियों को बात भी की फिर भी कारवाई नहीं हुई डीपी में शॉर्टकट होने से 2बजे लगी मांगीलाल जैपाराम जी देवासी की लकड़ी दो टोली लकड़ी जल कर राख हुई और स्थानीय लोगों ने गांव के टैंकर और अग्नि गाड़ी बुलाकर आग बुझाई ग्रामवासियों ने आग बुझाने में सोनराम बक्शा राम बुधाराम देवासी सरपंच भंवर लाल जी व भारी ग्रामवासियों मौजूद रहे।

पशु - पक्षियों के मरने से बिगड़ेगा प्रकृति का संतुलन, रक्षा करो उनकी तो सुख में होगा जीवन : डॉ उमेश शर्मा- चेयरमैन, उ.प्र. अपराध निरोधक समिति

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में अगर सबसे ज्यादा शामत किसी की आ रही है तो वे है बेजुबान पशु - पक्षी, इसीलिए बदलते पर्यावरण के बीच बेज़ुबान पशु - पक्षियों के लिए यह दौर चिंताजनक हो गया है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती इनको भयंकर गर्मी के मौसम में जल, भोजन और छाया की होती है। आओ हम इनके दाने - पानी, चारे - रोटी का इंतजाम कर इस नेक कार्य मे अपना छोटा सा योगदान अवश्य दे एवम इन बेजुबान प्राणियों की सेवा का नियम अपने जीवन मे अवश्य बनाये।

ये महत्वपूर्ण बात सुप्रशिद्ध एवं लोकप्रिय वरिष्ठ समाजसेवी एवं उ.प्र. अपराध निरोधक समिति लखनऊ के चेयरमेन डॉ उमेश शर्मा व उनका परिवार भी ख़ूब समझता हैं। उन्होंने इस सन्दर्भ में बताया कि नौतपा का समय आ गया है। हमारी सभी से प्रार्थना है की इस समय पशु-पक्षियों के लिए छाया, भोजन व जल की व्यवस्था अवश्य करें। क्योकि ताजनगरी और उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी का प्रकोप बरस रहा है। इस गर्मी से सिर्फ़ इंसान ही नहीं, बल्कि नन्हें-नन्हें पक्षी भी परेशान हैं। हर साल गर्मी के मौसम में न जाने कितने पक्षी प्यास और हीटस्ट्रोक का शिकार हो कर जान दे देते हैं। हम यदि एक छोटी-सी कोशिश करें, थोड़ी-सी मानवता दिखाएं और अपने घर-ऑफ़सि में आने वाले पक्षियों के लिए पानी और आश्रय का प्रबन्ध करें, तो गर्मी के कारण होने वाली पक्षियों की मौत में काफ़ी कमी आ सकती है। क्योकि पशु - पक्षियों के मरने से बिगड़ेगा प्रकृति का संतुलन, रक्षा करो उनकी तो सुख में होगा जीवन। इसलिए आज से जीवन में एक नियम बनाएं, पशु - पक्षियों को भी अपने घर का सदस्य बनाएं। बेजुबान पशु - पक्षियों के लिए छाया, पानी एवं भोजन का प्रबंध करें और इस भीषण गर्मी में बेजुबान पशु - पक्षियों की मदद के लिए आगे आएं।

आज से जीवन में एक नियम बनाएं, पशु – पक्षियों को भी अपने घर का सदस्य बनाएं :

बेज़ुबान पशु – पक्षियों के लिए छाया, पानी एवं भोजन का प्रबंध करें :

भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों की मदद के लिए आगे आएं :

प्रचंड गर्मी में बेज़ुबानों का हाल ना हो बेहाल, पशु – पंछीयों का भी रखें ख्याल :

बेजुबान प्राणियों की सेवा का नियम अपने जीवन मे अवश्य बनाएं : **डॉ उमेश शर्मा – चेयरमैन, उ.प्र. अपराध निरोधक समिति**

श्री शर्मा ने कहा कि प्रचंड गर्मी में बेजुबानों का हाल ना हो बेहाल, पशु - पंछीयों का भी रखें ख्याल। यदि एक छोटी-सी कोशिश करें और थोड़ी-सी मानवता दिखाएं और अपने घर- ऑफ़सि में आने वाले बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी और उनके चारा का प्रबन्ध करें, तो इस भयंकर गर्मी के कारण होने वाली पशु पक्षियों की मौत में काफ़ी कमी आ सकती है। इन बेजुबान पशु पक्षियों को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखें। आप सभी अपने आसपास पार्कों में, घर के छत पर चिडियों के लिए पीने का पानी मिटटी के बर्तन में अवश्य रखे। एक मिट्टी के बर्तन में पानी और एक प्लेट में चारा इस भयंकर गर्मी में चिड़ियों को थोड़ी सी छांव और प्यार से दें। लेकिन ध्यान रहे कि प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में पानी न रखें। धूप में इन बर्तनों का पानी बहुत गर्म हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में पानी रखना सबसे अच्छा होता है। इन बर्तनों की नियमित सफ़ाई करते रहें, ताकि पक्षी रोगों से दूर रहें और आज से जीवन में एक नियम बनाएं, पशु पक्षियों को भी अपने घर का सदस्य बनाएं और लोगों से भी यह करने का आग्रह करें आपके घर के बाहर कहीं भी पशु या पक्षी नजर आए तो उनकी भूख और प्यास अवश्य मिटाएं। पशु - पक्षी के मरने से बिगड़ेगा प्रकृति का संतुलन आओ मिलकर रक्षा करें उनकी तो सुखमय जीवन होगा।

उन्होंने आगे कहा कि पशु - पक्षीयो का भी ख्याल रखें। इस भयंकर गर्मी में इनके हाल बेहाल ना हो। तो आइएं हम सब इनके लिए छाया, दाने - पानी, चारे और रोटी का इंतजाम करे। हमारे घर के आस - पास के क्षेत्र में बेजुबान पशु - पक्षी भूखे ना रहे, हमारे घरों की छतों पर व आस पास के पेड़ो की छांव में परिंडे लगाए और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। इस नेक कार्य मे अपना छोटा सा योगदान अवश्य दे एवम इन बेजुबान प्राणियों की सेवा का नियम अपने जीवन मे अवश्य बनाये। इस भयंकर गर्मी में पक्षियों और जानवरों के लिए पीने का पानी ज़रूर रखें। छत पर एवम घर के बाहर एक हौद में पानी ज़रूर रखें। जब भी आप अपने रखे हुए पानी में किसी जीव को पानी पीते देखेंगे उस समय जो सुकून आपको मिलेगा उसका कोई जवाब नहीं। अगर ऐसा आज तक नहीं किया तो अब करके देखिये। मंदिर या देवालय के पास पक्षियों के दाना डालने की जगह ज़रूर बनवाएं। प्रतिदिन मंदिर जाते समय थोड़ा अनाज अवश्य डालें। कृपया आप सब भी रखे। कम से कम अपने घरो के बाहर गौ माता के लिए और छतो पर पंक्षियों के लिए पानी अवश्य रखिये। प्रचंड गर्मी को देखते हुये सभी से एक विनम्र निवेदन हैं कि आओ मिल कर गौ माता और समस्त बेजुबानों का दर्द थोड़ा बाटें, बस इसी प्रयास में, छत के ऊपर दाना-पानी, घर के बाहर बाल्टी एक पानी अवश्य रखें और इस मुहिम के साथ जुड़े व अन्यों को जोड़े ताकि कोई भी बेजुबान प्राणी भीष्ण गर्मी में प्यासा न रहें। क्योकि सेवा के इस महान और सराहनीय कार्य मे कोई मोल भी नही लगता तब भी ये अनमोल है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023